स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–3, फाल्गुन–चैत्र 2071–72, मार्च 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

वित्तमंत्री ने बजट के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा जाता रहा कि मोदी सिर्फ कारपोरेट घराने के लिए काम कर रहे हैं। पर बजट प्रस्तुत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर उद्योग जगत तक के लिए बहुत कुछ लेकर आई है. . .

कवर पेज

अ नु क्र म

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /2

आवरण कथा : बजट जनता को लुभाने के लिए नहीं दशा सुधारने के लिए जरूरी
– विक्रम उपाध्याय /6

दृष्टिकोण : सुखद स्थिति का मुश्किल बजट
– डॉ. अश्विनी महाजन /8

चर्चा :
भ्रम बढ़ाने वाला बजट
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /11

कृषि : ऐसे ही हालात रहे तो कोई क्यों करें खेती...
– शशांक द्विवेदी /13

सामयिकी : बेमौसमी बारिश से खेती–किसानी पर संकट
– प्रमोद भार्गव /15

उपलब्धि : मिसाइलों से लैंस होती हमारी सेनाएं
– लक्ष्मी शंकर यादव /17

विमर्श : मनरेगा का भ्रष्टाचार पर लगे रोक
– रवि शंकर /19

पहल : कालेधन के कारोबार पर लगेगी रोक
– ए. सूर्यप्रकाश /21

मुद्दा : फिर वही जोखिम
– ब्रह्मा चेलानी /23

विश्लेषण : संचार का तरीका बदलती तकनीक
– मुकुल श्रीवास्तव /25

पर्यावरण : परमाणु बिजली घरों का कचरा है बड़ी समस्या
– पंकज चतुर्वेदी /27

प्रतिक्रिया : पाकिस्तान में निशाने पर अल्पसंख्यक
– अरविन्द जयतिलक /29

अस्तित्व : आखिर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा क्यों
– महेशचन्द्र पुनेठा /32

अर्थतंत्र : देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश बढ़ाना मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती
– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल /34

पाठकनामा /4, समाचार परिक्रमा /36, रपट /37
स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियाँ /39,
स्वदेशी मेला /40

पाठकनामा

चिकित्सा क्षेत्र की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उसका भारतीकरण होना चाहिए

श्री भारत डोगरा जी द्वारा प्रदत्त लेख में चिकित्सा क्षेत्र में आई जिन विकृतियों का उल्लेख हुआ है वह निःसंदेह चिंता एवं चिंतन का विषय है। हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पश्चिम की सोच पर आधारित है अर्थात् जहाँ चिकित्सा एक व्यवसाय है तथा रोगी केवल मात्र एक उपभोक्ता है। भारत का दर्शन इससे बिल्कुल भिन्न है, यहाँ रोगी अपना ही बंधु है तथा चिकित्सा एक सेवा है। इस दर्शन को समझने के संस्कारों का होना अतिआवश्यक है। केवल संस्कारित व्यक्ति ही सेवा के महत्व को समझ सकता है तथा सेवा कर सकता है। अतः चिकित्सा क्षेत्र की इन दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उसका भारतीकरण होना चाहिए तभी शोषण होने के स्थान पर सही अर्थों में रोगी की सेवा हो पाएगी।

– उमेश शर्मा, सराथाना (कांगड़ा) हिमाचल प्रदेश

भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रयत्नशील

भ्रष्टाचार और काले पर रोक लगाने के लिए जितने प्रयास केन्द्र सरकार कर रही है उतने शायद पूर्व की यूपीए सरकार ने कभी किए ही नहीं। यूपीए ने कालेधन, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया था। मगर अब मोदी सरकार ने बजट में कालेधन पर सख्त कदम उठाए है। इसके अलावा कालेधन को जल्द से जल्द लाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों को काले धन और भ्रष्टाचार की चिंता कम और सरकार को काम करने से रोकने में आजकल ज्यादा रुचि है।

– सुधीर रावत, गाजियाबाद

हर दिन हो महिला दिवस

एक बार फिर 8 मार्च के दिन अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की रस्म अदायगी के साथ नारी सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की बातें मेरे मन में उठी रही थी। क्या आखिर यह सम्मान सिर्फ एक दिन के लिये ही क्यों? साल के बाकी 364 दिन क्यों नहीं महिला का इसी तरह सम्मान हो। आज महिलाएं मर्दो से कदम से कदम मिला कर चलने को तैयार है परंतु फिर भी दुनिया के तमाम देशों में महिलाओ की हैसियत दोयम दर्जे की है। आज जरूरत है कि महिलाओ के प्रति समाज को अपना नजरिया बदलना ही होगा। उसकी प्रशस्ति में महज एक दिन के गुणगान से कुछ नहीं बदलने वाला। हर दिन महिला के लिए हो तभी नारी शक्तिकरण होगा।

– भारती देवी, ए–1 ब्लॉक, गली नं. 8, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित क र ।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

हमें अपनी देश की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा तभी हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे।

– लक्ष्मण आचार्य

आज हम दुविधा में हैं जिसके कारण हम स्वदे ी विचार और संस्कृति के फायदे और नुकसान को नही समझ पा रहे हैं।

– बंदेशंकर सिंह

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस सहित अनेक विभूतियों ने देश को आजादी दिलाने में स्वदेशी को ही अपना हथियार बना।

– वीरेन्द्र सिंह

वित्त मंत्री को इस गरीब समर्थक, वृद्धि समर्थक, मध्यम वर्ग समर्थक, युवा समर्थक और समूचे परिदृश्य को बदलने वाले बजट के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

'बजट राजग सरकार के 'अच्छे इरादों' को जाहिर करता है लेकिन इसमें उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी स्पष्ट योजना का अभाव है।

– मनमोहन सिंह, पर्व प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री के विजन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को हम पूरा करेंगे।

– सुरेश प्रभु

प्रभु ने नई योजनाओं का ऐलान नहीं किया, बल्कि पिछले उपायों को अमली जामा पहनाने की बात कही है। अगर वो सफल रहते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी।

– मुलायम सिंह

संपादकीय

दहाई अंको की विकास दर में सब हो समाहित

बजट से ठीक एक दिन पहले आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई है। वित्तमंत्री अरूण जेटली का यह दावा कि एक दो वर्श में ही हमारी विकास दर 10 फीसदी से भी ऊपर जा सकती है। दाँवे के साथ एक और बयान की कि यह चमत्कार नौ महीने की भाजपा सरकार की देन है, लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि दस फीसदी की विकास दर में उनकी हिस्सेदारी कहां है। काम के बजाय अपनी पीठ थपथपाने में अवसरों को खूब खर्च करने से इस सरकार को अभी बचना चाहिए। नौ महीने मे सरकार ने जो निर्णय लिए उसका परिणाम सामने आने में समय लग सकता है। अभी तक की सभी आर्थिक उपलब्धियां परिस्थितिजन्य है न कि नीतिगत फैसलों का सुखद परिणाम। डीजल के मूल्य को नियंत्रण मुक्त करना, कच्चे तेल के दामों आई भारी कमी के बाद विदे ाी मुद्रा की बचत होना, रक्षा व बीमा क्षेत्र में विदे ाी निवे ा की सीमा बढ़ाना, कोल अध्यादे ा जारी कर नई नीलामी के जरिए मोटी रकम कमाना – ये सब एकल अवसर हैं। दे ा सिर्फ अपने प्राकृतिक संसाधनों को एकमुश्त बेचकर या जनता से ज्यादा उगाही कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों का चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ेगे। कृशि उपज दर नहीं बढ़ेगी। लघु उद्योग का कारोबार नहीं बढ़ेगा और आम आदमी की कमाई महंगाई दर से अधिक नहीं बढ़ेगी तब तक दे ा दहाई आंकड़े वाली विकास दर हासिल नहीं कर सकता। जब तक लोगों की बचत नहीं बढ़ेगी तब तक उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री नहीं बढ़ेगी। यह तो अच्छा हुआ कि सुधारों की बिग बैंग थ्योरी से सरकार ने किनारा कर लिया, क्योंकि सुधार एक सतत् प्रकिया है। किसी दे ा या किसी कॉरपोरेट घराने के दबाव में बिना सोचे समझे जिन सुधारों को लागू किए गए वे सही साबित नहीं हुए। सरकार को मालूम है कि संघ परिवार किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों को हानि पहुंचाने और विदे ाी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रावधान को हरगिज बर्दा त नहीं कर सकता । जरूरी है कि वित्तीय अनु ाासन और फिजूल खर्ची पर अंकु ा लगाने वाले प्रावधान हों। सब्सिडी की लूट तो बंद हो पर जरूरत मंद को सरकारी मदद मिलती रहे। केरोसिन की सब्सिडी पर खर्च होने वाली 10 हजार करोड़ की रा ि ा को बचाने के लिए सरकार को पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली और गैस कनेक् ान की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह अच्छी बात है कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की रा ि ा सीधे उनके बैंक में पहुंचाने का प्रयोग सरकार ने किया है जो काफी लाभदायक रहा है। इससे न सिर्फ सब्सिडी की बदंरबाट रूकेगी, बल्कि जरूरत मंदों को समय से सहायता भी मिलेगी। इस योजना में भाामिल होने के लिए राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे भी सामाजिक सुरक्षा को दी जाने वाली सहायता सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में भिजवाएं। सरकार को चाहिए कि किसानों को वह सीधे बाजार तक पहुंचाए। एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाकर सामान बेचने पर किसी भी प्रकार के अवरोध को समाप्त करने का प्रस्ताव सराहनीय हो सकता है। यही नहीं पूरे देश में एक समान कर और समय पर कर वसूली की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए जीएसटी को भी समय से लागू करने की आवश्यकता है।

बजट जनता को लुभाने के लिए नहीं दशा सुधारने के लिए जरूरी

वित्तमंत्री ने बजट के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा जाता रहा कि मोदी सिर्फ कारपोरेट घराने के लिए काम कर रहे हैं। पर बजट प्रस्तुत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर उद्योग जगत तक के लिए बहुत कुछ लेकर आई है. . .मोदी के स्कील इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्कील मिशन की स्थापना की घोषणा की गई। इस मिशन में केंद्र के कई मंत्रालयों की भूमिका होगी।

■ **विक्रम उपाध्याय**

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015 –16 के बजट को पेश करते हुए जब यह दावा किया कि विरासत में एक खराब अर्थव्यवस्था मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने देश को विकास के रास्ते पर डाल दिया है, जहां से ऊंची विकास दर के लिए उड़ान भरा जा सकता है, तो फिर कई सवाल मन में उठने लगे। क्या किसानों की हालत अब ठीक हो गई है, क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगी है, क्या श्रमिकों को काम मिलने लगे हैं, क्या विद्यार्थियों को उचित शिक्षा मिलने लगी है और सबसे बड़ी बात क्या अमीर–गरीब की खाई मिटने लगी है?

जाहिर है बजट में आंकड़ों और उदाहरणों से कोई ऐसे संकेत नहीं मिले। हां वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक जिन योजनाओं की घोषणाएं की हैं, उन सबके लिए वित्त का पर्याप्त इंतजाम हो।

वित्तमंत्री ने हालांकि आम नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन कर छूट के विभिन्न मदों की सीमा बढ़ाकर मध्य आय वर्ग को अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित जरूर किया। पिछले कुछ सालों में बचत की दर गिरी है। आम आदमी के लिए दर्जनों नई योजनाओं की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने दावा किया कि इस बजट से हर चेहरे पर मुस्कान लाने का उन्होंने प्रयास किया। वित्तमंत्री ने बजट के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया, जिसमें कहा जाता रहा कि मोदी सिर्फ कारपोरेट घराने के लिए काम कर रहे हैं। पर बजट प्रस्तुत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर उद्योग जगत तक के लिए बहुत कुछ लेकर आई है।

सबको मकान, मकानों में 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा, हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार, पूरे देश में शौचालय का निर्माण और एक रुपये महीने के सहयोग पर दो लाख का बीमा जैसे प्रावधान गरीबों के लिए किए गए हैं, वहीं ढांचागत क्षेत्र में भारी निवेश और इस निवेश के लिए अतिरिक्त धन जुटाने हेतु कर मुक्त बांड, सोना की खरीद बिक्री सरल करने, सोना को गिरवी रख कभी भी बैंकों से उधार प्रात करने जैसे प्रावधान मध्यवर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश ही है।

सबको मकान, मकानों में 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा, हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार, पूरे देश में शौचालय का निर्माण और एक रुपये महीने के सहयोग पर दो लाख का बीमा जैसे प्रावधान गरीबों के लिए किए गए हैं, वहीं ढांचागत क्षेत्र में भारी निवेश और इस निवेश के लिए अतिरिक्त धन जुटाने हेतु कर मुक्त बांड, सोना की खरीद बिक्री सरल करने, सोना को गिरवी रख कभी भी बैंकों से उधार प्रात करने जैसे प्रावधान मध्यवर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश ही है। यही नहीं भारी भरकम बजट और उदार तरीके से बनी परियोजनाओं के लिए आने वाले खर्च में अनुशासन बरतने की भी घोषणा बजट में की गई।

वित्तमंत्री ने अगले वर्ष तक राजकोषीय घाटे को तीन फीसदी के आसपास रखने का भी आश्वासन देश को दे दिया। महंगाई पर काबू रखने के लिए मुद्रा स्फीति की दर एक समान जरूरी है और इसके लिए वित्तमंत्री ने रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर आवश्यकता अनुसार रिजर्व बैंक के काम–काज की मॉनिटरिंग करने का भी ऐलान किया।

वित्तमंत्री ने एक तरफ आम आदमी को संतुष्ट करने का प्रयास बजट में किया वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट को भी उनकी मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी। वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट कर की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी। उद्योग जगत ने इस फैसले की जबर्दस्त बड़ाई करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इससे औद्योगिक गतिविधियों को नई

उड़ान मिलेगी। हालांकि उद्योग पर दो फीसदी का अधिभार भी लगाया गया है पर संपत्ति कर समाप्त होने और अन्य सुविधाओं के बहाल होने के बाद कॉरपोरेट जगत बहुत खुश है।

पूरा देश इस बजट पर टकटकी लगाए बैठा था। गांव के गरीब से लेकर बड़े–बड़े उद्योगपति इस बजट को गेम चेंजर के रूप में देख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। नौकरीपेशा लोगों को इस बात का इंतजार था कि इस बार कर की न्यूनतम सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया जाएगा, पर सीमा नहीं बढ़ाई जाने के बावजूद लोगों को मायूसी हाथ लगी, हालांकि कुछ अन्य करो में छूट के मदों की सीमा बढ़ा दी है। मसलन अब जीवन बीमा के 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम को आयकर से छूट प्राप्त होगी, इसके पहले यह सीमा 15 हजार थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही सीमा अब 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी गई है। 80 साल से अधिक की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब 30 हजार तक के मेडिकल खर्चें पर आय कर छूट प्राप्त होगी और किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में अब यह छूट सीमा की 60 हजार से बढकर 80 हजार होगी। पेंशन फण्ड में अब डेढ़ लाख तक के निवेश पर कोई कर देय नहीं होगा, पहले यह सीमा केवल एक लाख रुपये की थी। नौकरी पेशा वालों के लिए अब यातायात खर्च पर प्राप्त कर छूट को भी 800 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई । पर एक करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमली, एसोसिएशन ऑफ पर्सनंस, बीओइाई, सहकारी समितियां, फर्म और स्थानीय निकायों पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रावधान बजट में किया गया।

वित्तमंत्री ने जन धन योजना के साथ बहुत सारी सुविधाओं की भी बजट में घोषणा की। अब मनरेगा का पैसा भी सीध ो लाभार्थियों के खाते में ही जाएगा। यहीं नहीं पूरे देश को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत एक रुपये प्रति माह जमा कर कोई भी दो लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत अधिकतम एक हजार के प्रीमियम जमा करने पर सरकार 500 रुपये का अंशदान खुद करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के नाम से शुरू योजना में सामान्य और दुर्घटना के कारण होने वाले मृत्यु के बाद आश्रितों को लाभ देने की योजना है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का कोई व्यक्ति 330 रुपये प्रीमियम देकर दो लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है।

वित्तमंत्री ने अपने पूर्ववर्ती पी चिंदबरम की सोच को गलत कर दिया कि सोना के आयात पर ज्यादा शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इससे रुपये पर दबाव कम होगा। सोना के आवक जावक का आकलन करना काफी मुश्किल है। इसलिए देश की जनता को सोना खरीदने बेचने और गिरवी रखने के ढ़ेर सारे विकल्प बजट में दे दिए गए हैं। देश में इस समय 20 हजार टन से भी ज्यादा सोना है, उनका ना तो कारोबार होता है और न उनका मौद्रिक लाभ ही मिलता है। अब कोई भी सोना गिरवी रखकर लोन ले सकता है, उस पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। जब चाहे उसे बेच सकता है और यह सुविधा केवल आम उपभोक्ता को नहीं, बल्कि आभूषण व्यापारी को भी प्राप्त होगा। अब किसी को भौतिक रूप से सोना खरीदने की जरूरत नहीं होगी, चाहे तो वे गोल्ड बांड खरीद सकते हैं जिस पर उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज भी प्राप्त हो सकता है। विदेशों से सोने के सिक्के लाने की ललक रखने वाले को एक बेहतर विकल्प सरकार ने दे दिए है। अशोक चिन्ह के प्रतीक वाले सोने के सिक्के का देश में ही सरकार निर्माण करेगी।

चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार के आने के बाद देश में रोजगार के असीम अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्होंने उद्योग व व्यापार जगत को कई रियायतें बजट में प्रदान की। मुख्यतौर पर धातुएं, इंसुलेटेड वायर व केबल, रेफ्रिजरेटर, कम्प्रेशर और केटेलिक कनवर्टर के अवयवों के आयात व उत्पाद शुल्कों में कटौती की गई। यहीं आयरन व स्टील के मेटल स्क्रैप, तांबा, कांसा और अल्यूमिनियम के सैड (डिडक्शन एट सोर्स) की दर भी चार फीसदी से घटाकर दो फीसदी कर दी। एलईडी लाइट्स को बढ़ावा देने के लिए इस पर सैड ही खत्म कर दिया।

मोदी के स्कील इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्कील मिशन की स्थापना की घोषणा की गई। इस मिशन में केंद्र के कई मंत्रालयों की भूमिका होगी। कर्नाटक में एक नया आईआईटी और धनबाद के स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का पूर्ण दर्जा देने की भी घोषणा की गई। कश्मीर और आंध्र प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माईंस की भी स्थापना करने की बजट में घोषणा की गई है। अब देखना है कि इतनी सारी घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसा होता है। यह बजट सचमुच उड़ान का बजट बनता है, या लोगों को मायूस करता है। ❑

सुखद स्थिति का मुश्किल बजट

सरकार ने कहा है कि व्यापार, व्यवसाय को आसान बनाने के लिए नियमों को सुगम बनाया जाएगा और बिना वजह अनुमतियों के चक्कर में व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई दूर होगी, जिसे 'प्लग एंड प्ले मॉडल' का नाम वित्तमंत्री ने दिया है, देश में व्यापार, व्यवसाय और उत्पादन के लिए बेहतर वातावरण देगा, ऐसा माना जा सकता है। यह बजट सरकार राजकोष में आई भारी कमी की चुनौती के बावजूद एक ऐसा बजट कहा जा सकता है, जिसमें गरीब और छोटा काम करने वालों से लेकर बड़े–बड़े कारपोरेट को खुश करने की कोशिश की गई है।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

जीडीपी ग्रोथ दर इस साल 7.4 प्रतिशत और अगले साल 8 से 8.5 प्रतिशत अपेक्षित, 5 फीसदी उपभोक्ता महंगाई और शून्य पर पहुंचती थोक महंगाई और विदेशी भुगतान घाटा जीडीपी का मात्र 1.3 फीसदी रह जाना वास्तव में अनुकूल स्थितियों की तरफ इंगित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विदेशी निवेश का प्रवाह भी बढ़ रहा है और दुनिया का रूख भी भारत के बारे में बदला है। वित्तमंत्री ने यह भी कहा है कि अब भारत की उड़ने की बारी है, यह दुनिया मानती है।

आज अर्थव्यवस्था एक 'मधुर स्थिति' में है, जो कभी–कभार ही होता है। आज भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया की और ग्रोथ में आ रही तेजी के चलते परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी सरकार के खजाने में पैसा कम ही है। केन्द्र सरकार की आमदनी में थोड़ी वृद्धि होने के बावजूद 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकार को ज्यादा पैसा राज्यों को देना होगा, जिसके चलते उसके पास स्वयं के बजट के लिए पैसा कम बचेगा। पिछले साल के 3.8 लाख करोड़ की तुलना में राज्यों को 2015–16 में 5.8 लाख करोड़ मिलने वाला है। गौरतलब है कि 2014–15 के बजट में 17.9 लाख करोड़ का खर्च तय किया गया था (हालांकि वास्तविक खर्चा 16.81 लाख करोड़ ही हुआ); लेकिन इस बार के बजट में पिछले बजट से भी कम राशि खर्च के लिए रखी गई है, यानि 17.77 लाख करोड़। जाहिर है कि राज्यों को ज्यादा राशि देने के बाद केन्द्र सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा ही नहीं है।

लेकिन सरकार के पास पैसा है कम

तेल की घटती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों

स्थाई खर्चे हैं यथावत

सरकार को कई मदों पर खर्च करना निहायत जरूरी है, जैसे– ब्याज की अदायगी जरूरी है, जिसपर 4.56 लाख करोड़ रूपया जाना है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पुलिस, प्रतिरक्षा इत्यादि पर कुल खर्च हर बार की भांति बढ़ाया गया है। ऐसे में स्वभाविक ही है कि सरकार सामाजिक सेवाओं पर खर्च ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी।

सरकार को कई मदों पर खर्च करना निहायत जरूरी है, जैसे– ब्याज की अदायगी जरूरी है, जिसपर 4.56 लाख करोड़ रूपया जाना है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पुलिस, प्रतिरक्षा इत्यादि पर कुल खर्च हर बार की भांति बढ़ाया गया है। ऐसे में स्वभाविक ही है कि सरकार सामाजिक सेवाओं पर खर्च ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी।

उच्च शिक्षा पर पिछले साल के बजट से मात्र 244 करोड़ रूपए ही ज्यादा खर्च का प्रावधान है, जबकि स्कूली शिक्षा पर पहले से 100 करोड़ रूपया कम खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य पर भी खर्च मामूली बढ़ा है। माना जा सकता है कि सरकार पर इन खर्चों को कम करने के लिए खासा दबाव रहा होगा।

काले धन पर कड़ा लेकिन कारपोरेट पर नरम

बजट में विदेशों में कालाधन रखने वालों पर कड़ाई से निपटने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। विदेशों में कालाधन रखने पर सजा का प्रावधान वास्तव में अच्छा कदम है, जो लोगों को देश का पैसा बाहर ले जाने के लिए हतोत्साहित करेगा। लेकिन कंपनियों पर यह बजट मेहरबान दिखाई दिया और कारपोरेट कर की दर को अगले चार सालों में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की बात की गई है। यह बात दूसरी है कि साथ ही साथ कारपोरेट को मिलने वाले छूटों को कम करने की बात भी बजट में की गई है। यानि कहा जा सकता है कि कारपोरेट पर यह बजट खासा नरम रूख अपना रहा है।

गौरतलब है कि यदि वैयक्तिक आयकर में छूट, जो 2014–15 में 40,435 करोड़ रूपए थी और लघु उद्योगों को मिलने वाली उत्पाद शुल्क में छूट, जो कारपोरेट कर दाताओं के छूटों के तुलना में दसवां हिस्सा भी नहीं है, को निकाल दिया जाए तो केन्द्रीय कर प्रणाली के केन्द्रीय राजस्व पर पड़ने वाला अधिकतर प्रभाव कारपोरेट जगत को मिलने वाली छूटों के कारण है। वर्तमान में जबकि केन्द्र सरकार के पास राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद बहुत कम राजस्व बचता है, ऐसे में कारपोरेट जगत को दी जाने वाली अनावश्यक छूटों को कम करने का विशेष किया जाना जरूरी हो गया है। हालांकि इस बजट में वित्तमंत्री ने इस बावत कुछ घाषणाएं की हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक काम करने की जरूरत है।

तालिका 1: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव (केन्द्र सरकार) (2009–10 से 2014–15)

(करोड़ रूपयों में)

	2009–10	2010–11	2011.12	2012.13	2013.14	2014.15
निगम कर	72,881	57,912	61,765	68,720	76,116	62,399
वैयक्तिक आयकर	45,142	36,826	39,375	33,536	40,414	40,435
उत्पाद शुल्क	1,69,121	1,92,227	1,95,590	2,90,940	1,95,679	1,84,764
सीमा शुल्क	1,95,288	1,72,740	2,36,852	2,54,039	2,60,714	3,01,688
कुल	4,82,432	4,59,705	5,33,582	5,66,235	5,72,923	5,89,286

स्रोत : केन्द्र सरकार का बजट 2015–16 एवं पूर्व के बजट दस्तावेज

घाटा घटने से महंगाई पर अंकुश

पिछले वर्षों में राजकोषीय घाटा खासा बड़ा रहता रहा है। पिछले साल के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह जीडीपी का 4.1 प्रतिशत रहा। बजट में वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को अगले साल 3.9 प्रतिशत और अगले तीन सालों में 3 प्रतिशत तक ले जाने की बात कही है। गौरतलब है कि राजकोषीय घाटा वर्ष 2008–09 में 6.0 प्रतिशत तक पहुंच गया था। पिछले सालों में लगातार बढ़ती महंगाई के पीछे यह एक प्रमुख कारण था। गौरतलब है कि इस घाटे की पूरी भरपाई उधार से न कर पाने के कारण सरकार को रिजर्व बैंक से ऋण लेना पड़ता है और इस कारण से ज्यादा नोट छपते हैं और महंगाई बढ़ती है। पिछले 4 साल का जायजा यदि लें तो हर साल करैंसी की मात्रा 9 से 17 प्रतिशत तक बढ़ी, जो महंगाई का प्रमुख कारण रही। आशा की जा सकती है कि राजकोषीय घाटे को काबू में रखने की प्रतिबद्धता आम आदमी के लिए

तालिका 2 : केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	राजकोषीय
2009–10	414041 (6.0)
2010–11	373591 (4.9)
2011–12	521980 (5.9)
2012–13	520925 (5.2)
2013–14	502858 (4.4)
2014–15 (संशोधित)	512628 (4.1)
2015–16 (बजट)	555649 (3.9)

स्रोत : केन्द्र सरकार के विभिन्न बजट।

तालिका 3 : जनता के पास कैरेंसी की मात्रा

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	जनता के पास कैरेंसी मात्रा
2009–10	768049
2010–11	914170
2011–12	1067890
2012–13	1145490
2013–14	1248340
दिसम्बर 12, 2014	1335820

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न मासिक बुलेटिन और केन्द्र सरकार के विभिन्न बजट।

महंगाई पर अंकुश लगाएगी।

'मेक इन इंडिया'

'मेक इन इंडिया' इस सरकार का नारा रहा है, जिसका मतलब है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन। गौरतलब है कि आज हमारे टेलीकॉम के आयात 100 अरब डालर तक पहुंच रहे हैं, आज देश में कम्प्यूटर चिप से लेकर कम्प्यूटर, मोबाईल फोन समेत विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम उत्पाद आयात किए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन वस्तुओं के आयात पर कम शुल्क लगता है, जबकि देश में उत्पादन करने पर ज्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, यह बात पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्वीकार की गई। ऐसे में स्वभाविक ही था कि सरकार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुसार इस विसंगति को दूर करे। बजट में आयातित स्पेयर पार्ट पर शुल्क कम करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे 'मेक इन इंडिया' को बल मिलेगा और तैयार माल के आयात घटेंगे। इसके साथ ही यह जरूरी था कि विदेशों से इन वस्तुओं के आयातों पर शुल्क को बढ़ाया जाता ताकि भारत में बना सामान प्रतिस्पर्धा में टिक सके।

मध्यम वर्ग को निराशा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के दौरान यह संकेत दिया गया था कि आयकर की छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्व की कमी के दबाव के चलते सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम में निवेश और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने पर कर में छूट जरूर बढ़ाई गई है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट एलाउंस पर छूट की सीमा भी बढ़ी है, जिसका थोड़ा बहुत फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा।

लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की अनदेखी हुई हो। छोटे और माइक्रो उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा बढ़ाने हेतु 'मुद्रा बैंक' की स्थापना और उसके लिए 20,000 करोड़ रूपए का प्रावधान व्यापार और छोटे उद्योगों में लगे मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सुविधा लाएगा, ऐसा माना जा सकता है। गरीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान जैसे– 12 रूपए सालाना देकर 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 365 रूपए देकर 2 लाख का सामान्य बीमा (प्राकृतिक मृत्यु), वृद्धावस्था पेंशन हेतु सरकार द्वारा अंश दान कुछ ऐसे कदम हैं जो गरीबों के हित में कहे जा सकते हैं।

हालांकि सरकार ने कहा है कि व्यापार, व्यवसाय को आसान बनाने के लिए नियमों को सुगम बनाया जाएगा और बिना वजह अनुमतियों के चक्कर में व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई दूर होगी, जिसे 'प्लग एंड प्ले मॉडल' का नाम वित्तमंत्री ने दिया है, देश में व्यापार, व्यवसाय और उत्पादन के लिए बेहतर वातावरण देगा, ऐसा माना जा सकता है। यह बजट सरकार राजकोष में आई भारी कमी की चुनौती के बावजूद एक ऐसा बजट कहा जा सकता है, जिसमें गरीब और छोटा काम करने वालों से लेकर बड़े–बड़े कारपोरेट को खुश करने की कोशिश की गई है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

भ्रम बढ़ाने वाला बजट

वित्तमंत्री ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शीघ्र लागू करने पर जोर दिया है। उद्यमियों की दृष्टि से यह अच्छा है, परंतु तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या राज्यों की स्वायत्तता की है। वर्तमान में हर राज्य द्वारा माल पर लगने वाले टैक्स को स्वयं निर्धारित किया जाता है। हर राज्य को डीजल और सिगरेट पर अलग–अलग दर से टैक्स लगाने की छूट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में राज्यों की यह स्वायत्तता छीन ली जाती है। केंद्र सरकार द्वारा हर माल पर लगने वाले टैक्स की दर को निर्धारित कर दिया जाएगा जो कि पूरे देश पर लागू होगा।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

बजट के कुछ सकारात्मक पहलुओं तथा मेक इन इंडिया की समस्याओं के संबंध में कुछ बातें पहले ही आ चुकी हैं। बुनियादी संरचना तथा रक्षा क्षेत्र के बजट में मामूली वृद्धि की गई है जो कि महंगाई के प्रभाव के सामने शून्य प्राय हो जाती है। इन मदों पर खर्च में बहुत ज्यादा वृद्धि की जरूरत है।

पिछले वर्ष यदि रक्षा बजट 100 करोड़ था और महंगाई 6 प्रतिशत तो उतनी ही क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए इस वर्ष का रक्षा बजट 106 करोड़ होना चाहिए था। वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तावित मामूली वृद्धि से तो बुनियादी संरचना तथा रक्षा बजट की पूर्व क्रयशक्ति भी नहीं बनी रहेगी।

तेल पर मामूली टैक्स बढ़ाकर सड़क पर निवेश बढ़ाने का सार्थक कदम उठाया गया है जिसका स्वागत है। इस समय विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी गहरा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष आदि संस्थाओं ने अगले वर्ष के ग्रोथ के अनुमान घटा दिए हैं। इस कारण तेल की मांग कम हो रही है और दाम गिरे हुए हैं। ऐसे में वित्तमंत्री के सामने दो रास्ते थे। वे तेल के दाम की गिरावट को उपभोक्ता को दे सकते थे। ऐसे में तेल के घरेलू दाम कम होंगे और खपत बढ़ेगी। हम आयातित तेल पर च्यादा निर्भर हो जाएंगे और हमारी ऊर्जा सुरक्षा नष्ट हो जाएगी।

दूसरा रास्ता था कि तेल पर भारी टैक्स आरोपित किया जाता और वसूल की गई रकम को थोरियम से ऊर्जा बनाने, न्यूक्लियर वेस्ट को रीसाइकिल करने अथवा सोलर पैनल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तब हमारी ऊर्जा सुरक्षा कायम होती। दुर्भाग्य है कि वित्तमंत्री ने तेल के दाम में मामूली वृद्धि करके जनता को भ्रमित किया है और देश को ऊर्जा परतंत्र बनाने का कदम उठाया है।

मनरेगा पर 34 हजार करोड़ का आवंटन पूर्व के बराबर है। वृद्धि न करके वित्तमंत्री ने इस जनहितकारी योजना के पर काटने की ओर कदम उठाया है उसी तरह जैसे दुश्मन के भोजन के रास्ते रोक कर मृत्यु के घाट उतारा जाता है। वित्तमंत्री ने स्वीकार किया है कि पर्यावरण की हानि का सीधा दुष्प्रभाव गरीब पर पड़ता है। इस स्वीकारोक्ति के लिए बधाई। इस दिशा में बिजली से चलने वाली कार को बढ़ावा देने के लिए राई बराबर 75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसका स्वागत है। परंतु पर्यावरण समेत नमामि गंगे को केवल 4100 करोड़ का आवंटन किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जरूरत थी कि प्रदूषण न करने वाली इकाइयों को टैक्स में छूट दी जाती। नमामि गंगे के नाम पर किया गया आवंटन गंगा की रक्षा के लिए है अथवा मर्डर के लिए, यह भी स्पष्ट नहीं है।

पिछले बजट में गंगा पर तमाम नए बांध बनाकर गंगा जल मार्ग पर ढुलाई को प्रोत्साहन देकर गंगा का मर्डर करने के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया

गया था। संभव है कि इस बार भी ऐसा ही हो। वित्तामंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि जो रकम आवंटित की गई है उसका उपयोग किस प्रकार होगा।

वित्तमंत्री ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शीघ्र लागू करने पर जोर दिया है। उद्यमियों की दृष्टि से यह अच्छा है, परंतु तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या राज्यों की स्वायत्तता की है। वर्तमान में हर राज्य द्वारा माल पर लगने वाले टैक्स को स्वयं निर्धारित किया जाता है। हर राज्य को डीजल और सिगरेट पर अलग–अलग दर से टैक्स लगाने की छूट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में राज्यों की यह स्वायत्तता छीन ली जाती है। केंद्र सरकार द्वारा हर माल पर लगने वाले टैक्स की दर को निर्धारित कर दिया जाएगा जो कि पूरे देश पर लागू होगा। जैसे पंजाब यदि डीजल पर टैक्स ज्यादा और हवाई चप्पल पर टैक्स कम लगाना चाहे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद नहीं कर सकेगा।

यह कदम सरकार के राज्यों के प्रति सकारात्मक दिखने वाले मुखौटे का पर्दाफाश करता है। जबसे नरेंद्र मोदी दिल्ली पर पदासीन हुए हैं वह राज्य विरोधी हो गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वह राज्यों की स्वायत्तता के हिमायती थे। दिल्ली पर सत्तारूढ़ होने के बाद वह राज्यों की स्वायत्तता के विरोधी हो गए हैं।

दूसरी समस्या गरीब वर्ग की है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अधिकाधिक माल पर एक ही दर से टैक्स आरोपित किया जाएगा जैसे गरीब की हवाई चप्पल और अमीर के डिजाइनर शूज पर। यह प्रणाली गरीबों के उत्पीड़न की है। गरीब और अमीर को एक ही लाठी से हांका जाएगा। तीसरी समस्या सेवा क्षेत्र पर प्रहार की है। देश का भविष्य सर्विसेज क्षेत्र में है, न कि मैन्यूफैक्चरिंग में। हमारे पास मैन्यूफैक्चरिंग के विस्तार के लिए भूमि, ऊर्जा तथा पानी नहीं है। मैन्यूफैक्चरिंग द्वारा बनाए गए प्रदूषण को वहन करने की भी शक्ति हमारे में नहीं है। इसकी तुलना में सर्विसेज में हम अव्वल हैं। हमारी संस्कृति मनुष्य की बुद्धि को तीव्र करती है जैसे माथे पर टीका लगाकर अथवा दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके। देश को अपनी इस बौद्धिक शक्ति का निर्यात करना चाहिए, न कि अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों का।

दूसरे देशों से कोयला, फर्टिलाइजर, गोबर आदि का आयात करके इन संसाधनों को साफ्टवेयर में परिवर्तन करके इनका निर्यात करना चाहिए। इस दिशा में मैन्यूफैक्चरिंग पर टैक्स बढ़ाकर सर्विसेज पर घटाना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था इस सुदिशा में मुड़े। परंतु हर माल पर एक दर से टैक्स लगाने के संकल्प में वित्तामंत्री ने सर्विसेज पर टैक्स में वृद्धि की है।

बात वर्ष 2002 की है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि द्वारा बनाई गई पालिसी लागू की जा रही थी। आम आदमी त्रस्त था यद्यपि देश स्वर्णिम चतुर्भुज तथा परमाणु विस्फोट जैसी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। सलाहकारों द्वारा वाजपेयी के सामने रोजगार सृजन के फर्जी आंकड़े परोसे जा रहे थे। इन सलाहकारों द्वारा बनाए गए दलदल में वाजपेयी फंस गए। अंततः जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी अच्छी योजनाएं भी धीमी हो गईं। देश दस वर्ष पीछे पहुंच गया। इस बजट में मेक इन इंडिया तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स द्वारा रोजगार और छोटे उद्यमियों के हनन का पूरी ब्लूप्रिंट दिख रहा है। छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों की मेक इन इंडिया की भट्टी में झोंककर ऋण देने से रोजगार नहीं बढ़ेंगे। बड़ी कंपनियों द्वारा बाजार में सस्ता माल बेचा जाएगा। ऐसे में ऋण देकर वित्तामंत्री उसे और अधिक गहरे दलदल में धकेल रहे हैं।

बात वर्ष 2002 की है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि द्वारा बनाई गई पालिसी लागू की जा रही थी। आम आदमी त्रस्त था यद्यपि देश स्वर्णिम चतुर्भुज तथा परमाणु विस्फोट जैसी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। सलाहकारों द्वारा वाजपेयी के सामने रोजगार सृजन के फर्जी आंकड़े परोसे जा रहे थे। इन सलाहकारों द्वारा बनाए गए दलदल में वाजपेयी फंस गए। अंततः जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी अच्छी योजनाएं भी धीमी हो गईं। देश दस वर्ष पीछे पहुंच गया।

वितमंत्री को रोजगार भक्षक बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि मोदी के नेतृत्व में वाजपेयी का घटनाक्रम पुनः घटित होने की ओर बढ़ रहा है। यह बजट आम आदमी के संकटमय भविष्य की पूर्व सूचना दे रहा है। अमीर और अमीर होगा, कैबिनेट के उद्यमी मंत्री मालामाल होंगे, परंतु आम आदमी को सपनों से संतुष्ट होना पड़ेगा।❑

ऐसे ही हालात रहे तो कोई क्यों करें खेती. . .

हमारा किसान या तो कर्ज और तंगहाली में जी रहा है या फिर आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए आज कोई भी किसानी नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब किसान उगाएगा नहीं तो लोग खायेंगे क्या। एक बड़ी आबादी के खाद्यान्न की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? साफ है कि देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है जहां कोई किसानी नहीं करना चाहता, लेकिन खाना सबको है। इस गंभीर विषय पर समय रहते केंद्र और राज्य सरकारों को संजीदा होना होगा और इस पर व्यावहारिक रणनीति बनानी होगी ।

■ **शशांक द्विवेदी**

देश में खेती–किसानी के हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय कृषि से जुड़ी दो महत्वपूर्ण चीजें हुई– एक, करनाल में आयोजित 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और दूसरी, कृषि से जुड़ी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। करनाल में आयोजित कृषि विज्ञान कांग्रेस में खेत–किसान से जुड़ी चिंताओं पर चिंतन हुआ। चार दिन तक चले इस सम्मेलन में देश–विदेश के करीब लगभग 1500 डेलीगेट्स शामिल हुए और करीब 70 शोध पत्र प्रस्तुत हुए। मूल सवाल यह रहा कि मौजूदा परिवेश में कौन किसानी करना चाहेगा जिसका भविष्य कर्ज और तंगहाली के रूप में सामने आता हो।

पिछले दिनों आई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 52 फीसद कृषि पर आश्रित परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। कृषक परिवारों का घरेलू औसत कर्ज जहां 47,000 रुपए वार्षिक है, वहीं उनकी कृषि से वार्षिक आय महज 36,972 रपए है। एनएसएसओ द्वारा ऐसी रिपोर्ट हर 10 साल के अंतराल पर जारी की जाती है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पिछले पांच वर्षो के आंकड़ों के मुताबिक 2009 में 17 हजार, 2010 में 15 हजार, 2011 में 14 हजार, 2012 में 13 हजार और 2013 में 11 हजार से अधिक किसानों ने अपनी खेती–बाड़ी की तमाम दुश्वारियों के चलते आत्महत्या की राह चुन ली। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला यों तो पूरे देश में जारी है, पर कुछ पांच राज्यों– महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या दर सबसे अधिक रही है। 2009 में आत्महत्या के 62 फीसद मामले इन्हीं पांच राज्यों के रहे। इसके अलावा गुजरात और पंजाब में भी किसान मौत को गले लगाते रहे हैं, मगर महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है।

हमारा किसान या तो कर्ज और

हमारी कृषि का भविष्य छोटे किसानों के हाथों में ही है। इस समय 52 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। आजादी के समय कृषि का जीडीपी में योगदान 52 प्रतिशत तक था। लेकिन अब यह घटकर करीब 14.5 प्रतिशत रह गया है। आज के हालात में किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी निर्भरता घटे और उनका जीवनस्तर सुधरे।

तंगहाली में जी रहा है या फिर आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए आज कोई भी किसानी नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब किसान उगाएगा नहीं तो लोग खायेंगे क्या। एक बड़ी आबादी के खाद्यान्न की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? साफ है कि देश एक बड़े संकट की तरह बढ़ रहा है जहां कोई किसानी नहीं करना चाहता, लेकिन खाना सबको है। इस गंभीर विषय पर समय रहते केंद्र और राज्य सरकारों को संजीदा होना होगा और इस पर व्यावहारिक रणनीति बनानी होगी ।

फिलहाल चालू वित्त वर्ष में देश में अनाज उत्पादन में 85 लाख टन कमी की आशंका जताई गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले तीन फीसद की कमी है। इस अनुमान से देश में विकास दर में कमी आने और किसानों के लिए और संकट की स्थिति आने की आशंका है।

पिछले कुछ समय से देश की विकास दर को बढ़ाने में कृषि क्षेत्र का बड़ा हाथ रहा है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन लगातार उतार–चढ़ाव ही झेलता रहा है। किसानों के लिए संकट की बात यह है कि पूरी दुनिया में अनाज के भाव कम हुए हैं। ऐसे में उत्पादन घटने के बावजूद भारत में फसल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर उत्पादन घटेगा तो किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति किसान आत्महत्या की दर बढ़ा सकती है। इस वर्ष गेहूं उत्पादन मामूली रूप से घटकर नौ करोड़ 57.6 लाख टन रह जाने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में नौ करोड़ 58.5 लाख टन था। चालू वर्ष में प्रमुख खरीफ फसल चावल का उत्पादन 36.1 लाख टन घटकर 10 करोड़ 30.4 लाख टन रह जाने का अनुमान है जो पिछले वर्ष रिकार्ड 10 करोड़ 66.5 लाख टन के स्तर पर था।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक यह गिरावट वर्ष 2014 में मानसून सत्र के दौरान अनियत बरसात की स्थिति के कारण है। गौरतलब है कि इस वर्ष मानसून की बरसात में 12 प्रतिशत की कमी रह गई थी। बहरहाल, देश में मौजूदा कृषि और आसन्न खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सबसे पहले खेती पर आबादी के बड़े हिस्से की निर्भरता को कम करना होगा। उन्हें कृषि से जुड़े दूसरे रोजगार मुहैया कराने होंगे ताकि खेती को मुनाफे वाला पेशा बनाया जा सके। देश में करीब 85 फीसद खेती करने वाले छोटे किसान हो चुके हैं। भारत में 13.78 करोड़ कृषिभूमि धारकों में से लगभग 11.71 करोड़ छोटे–मझोले स्तर के किसान हैं। देश के आर्थिक–औद्योगिक खाद्यान्न संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में इस विशाल समुदाय का योगदान अहम है।

हमारी कृषि का भविष्य छोटे किसानों के हाथों में ही है। इस समय 52 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। आजादी के समय कृषि का जीडीपी में योगदान 52 प्रतिशत तक था। लेकिन अब यह घटकर करीब 14.5 प्रतिशत रह गया है। आज के हालात में किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी निर्भरता घटे और उनका जीवनस्तर सुधरे।

भारत जैसे देश में जहां आधी आबादी खेती पर निर्भर है वहां समांतर रोजगार के नए विकल्पों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। आने वाले दशकों में खाद्यान्न जरूरतों में वृद्धि के चलते वैकल्पिक खाद्य वस्तुओं मसलन डेयरी उत्पादों, मत्स्य व पोल्ट्री उत्पादों के विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को भूमि व पानी के अंधाधुंध दोहन से बचना चाहिए। सरकार को अपनी सक्षम नीतियों द्वारा छोटे किसानों को नियंत्रण स्पर्धा से मुकाबले लायक बनाना चाहिए। दरअसल, तमाम चुनौतियों से मुकाबले के लिए समग्र कृषि नीति बनाए जाने की आवश्यकता देश में महसूस की जा रही है। उच्च दर से अन्न उत्पादन से ही गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

अभी और आगे आने वाले समय में खाद्यान्न कमी की चुनौती को गंभीरता से लेने का समय आ गया है । देश में खेती करने का पैटर्न भी अब बदलना होगा, मसलन अब कई किसानों को साथ मिलकर सामुदायिक खेती करनी होगी जिससे वे लागत का बंटवारा आपस में कर सकें और मुनाफा भी बांट सकें। इससे वे बड़े स्तर पर खेती कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इस मुद्दे पर भी गहन मंथन करना होगा। इसके अलावा, देश में कृषि अनुसंधान को बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना होगा जिससे वे खेती के नए–नए तरीके ईजाद कर सकें। कुल मिलाकर खेती–किसानी को भी एक व्यवसाय के तौर पर स्थापित करना होगा, तभी लोग किसानी करने की तरफ आकृष्ट होंगे और देश में खाद्यान्न उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि होगी।

आज किसानों का जीवनस्तर ऊंचा उठाए बिना देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि देश की आधी से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। ऐसे हालात में कोई क्यों करे खेती!❑

बेमौसमी बारिश से खेती-किसानी पर संकट

पिछले साल सूखे से लड़ने वाला किसान अक्टूबर–नवम्बर आते–आते ओले और बेमौसम बरसात से तबाह हो गया था। इससे वह उबर भी नहीं पाया था कि बरसात ने तबाही मचाकर फसलें चौपट कर दी। इस तबाही की चपेट में घर और मवेशी भी आए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का खजाना खाली है और केंद्र सरकार की मदद इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि नियमों के मुताबिक केंद्र किसी राज्य की तभी मदद कर सकता है, जब फसलों पर 65 मिलीमीटर से ज्यादा बेमौसम बरसात की मार पड़ी हो।

■ **प्रमोद भार्गव**

गत सप्ताह पूरे देश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खेती–किसानी जबरदस्त संकट में हैं। इस संकट को भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक लापरवाही ने किसान को बेहद मायूस कर दिया है। किसान को जहां खरीफ फसल की बोआैनी के दौरान सूखे ने परेशानी में डाला वहीं इस ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात ने किसान को लगभग तबाह कर दिया है। इस कुदरती आपदा का असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में देखने में आया है। इस कारण जहां रवि फसलों की पैदावार में 20 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, वहीं दलहन उत्पादनों में 7 फीसद तक हानि की आशंका जताई जा रही है।

जाहिर है, मौसम की यह मार जहां फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी,वहीं महंगाई बढ़ाने वाली भी साबित होगी। मौसम की मार से गेहूं, चना, मसूर, सरसों, धनिया, मटर, संतरा और आलू की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस साल वैसे भी देरी से बारिश होने के कारण समय पर रवि फसलों की बुबाई नहीं हो पाई थी।

नतीजतन, कृषि मंत्रालय को पैदावार पिछली साल 10,60,65000 टन की तुलना में इस साल 10,03,40000 टन होने की उम्मीद थी, किंतु अब इसमें और गिरावट की उम्मीद बढ़ गई है। जाहिर है, इस बार रवि फसलों की पैदावार में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी जबकि दालों में 7 प्रतिशत की पैदावार कम होने की उम्मीद है। इस कारण कृषि मंत्रालय के

ताजा अनुमान के अनुसार इस साल देश का दलहन उत्पादन 184.3 लाख टन रह जाएगा।

पिछले साल यह उत्पादन 197.8 लाख टन था। इस साल तुअर का उत्पादन 27 लाख टन और चने का उत्पादन 10 प्रतिशत घटकर 82.8 लाख टन रहने के आसार हैं। कोटा–बूंदी के लोक सभा सांसद ओम बिरला ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में हुई भारी बारिश से नष्ट फसलों का मामला संसद में उठाकर किसानों को लागत के आधार पर मुआवजे की मांग केंद्र सरकार से की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ज्यादा तरजीह नहीं दी। जबकि उत्तर प्रदेश में तो फसल की बुरा हाल देखकर एक किसान आत्महत्या भी कर चुका है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है, जिससे किसानों की रोजी–रोटी चलती है। यहां के किसान की आमदनी का प्रमुख साधन रबी ही है। बेमौसम बरसात के पहले तक गेहूँ समेत दलहन और आलू की फसलें बेहतर थीं। किसान को उम्मीद थी कि इस बार उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन कुदरत की मार ने अन्नदाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 फीसद तक के नुकसान का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है,

जिसकी भरपाई न तो केंद्र करने को तैयार है और न ही उत्तर प्रदेश सरकार।

इस असामान्य बारिश से मध्य प्रदेश के किसान भी बुरे हाल में हैं। कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं–चना की फसल खेत में ही बिछ गई है। इससे दाने में दाग लगने या दाने छोटे रह जाने की आशंका बढ़ गई है। चना और मसूर के साथ धनिया और सब्जियों के लिए भी यह बारिश जानलेवा साबित हुई है। प्रदेश में इस साल 54 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है। जिन किसानों ने सिंचाई सुविधा के चलते बोवनी पहले की थी, उनकी फसल पक जाने के कारण कटने की स्थिति में है। जो अचानक बारिश से गीली होकर एवं पानी की मार से खेतों में बिछ गई। इससे दाना कमजोर तो पड़ेगा ही, उसमें दाग भी आ जाएंगे। लिहाजा, किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। फसल का यह नुकसान ग्वालियर–चंबल संभाग से लेकर महाकौशल व विंध्य तथा मालवा–निमाड़ तक में भी है।

मौसम की यह मार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने जलवायु प्रसार का असर बताया जा रहा है। इस विक्षोभ का 90 प्रतिशत तक गेहूँ की फसल पर असर पड़ा है। इस बार किसानों पर मार इसलिए भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि फसल के दागी होने के कारण किसान को बाजिव मूल्य मिलने वाला नहीं है। दूसरे, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग बंद कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के कई जिलों में मनरेगा योजना से भी हाथ खिंच लिए गए हैं। गोया तय है किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों को राहत कार्यों से होने वाली आमद भी बंद हो गई है। मसलन किसान चौतरफा आर्थिक संकट से घिरा अनुभव कर रहा है। मध्य प्रदेश में यह हालत उस किसान की है, जिसका मध्य प्रदेश की जीडीपी दर में योगदान 24 फीसद है और पिछले चार साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि कर्मण पुरस्कार लेकर खेतीकि सानी का गौरव–गान करने में लगे हैं। बावजूद प्रदेश सरकार खेती–किसानी की चिंता के बजाय उद्योगपतियों की चिंता में कुछ ज्यादा ही लगे हैं।

मौसम की यह मार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने जलवायु प्रसार का असर बताया जा रहा है। इस विक्षोभ का 90 प्रतिशत तक गेहूँ की फसल पर असर पड़ा है। इस बार किसानों पर मार इसलिए भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि फसल के दागी होने के कारण किसान को बाजिव मूल्य मिलने वाला नहीं है। दूसरे, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग बंद कर दिया है।

जरूरत है कि प्रदेश सरकार कृषि और कृषि आधारित उद्योग–धंधों पर ज्यादा ध्यान दे ताकि किसान को फसलों का अच्छा मूल्य मिले और कृषि लाभ का धंधा साबित हो। प्रदेश में खेती–किसानी की हालत लगातार बदतर हो रही है। सिंचाई का रकवा बढ़ने के बावजूद 64 प्रतिशत कृषि भूमि अब भी असिंचित है। खेतों के आकार भी घट रहे हैं।

वर्ष 2000–01 में जहां प्रदेश में औसत जोत का आकार 2.22 हेक्टेयर था, वहीं 2010–11 में यह घटकर 1.78 हेक्टेयर रह गया है। एक कृषि सर्वे के अनुसार पूरे प्रदेश में महज एक प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन है जबकि लगभग 72 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके खेतों का रकवा 2 हेक्टेयर से कम है। साफ है, किसान की हरेक स्तर पर हैसियत सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में मौसम की मार किसान की आर्थिक लाचारी को और बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे ही हालातों के चलते मध्य प्रदेश में भाजपा के पिछले एक दशक के कार्यकाल में लगभग 11 हजार किसान कृषि संबंधी मजबूरियों के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। इस बेमौसम बारिश की मार से महाराष्ट्र का किसान भी बदहाली का शिकार हुआ है।

पिछले साल सूखे से लड़ने वाला किसान अक्टूबर–नवम्वर आते–आते ओले और बेमौसम बरसात से तबाह हो गया था। इससे वह उबर भी नहीं पाया था कि बरसात ने तबाही मचाकर फसलें चौपट कर दी। इस तबाही की चपेट में घर और मवेशी भी आए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का खजाना खाली है और केंद्र सरकार की मदद इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि नियमों के मुताबिक केंद्र किसी राज्य की तभी मदद कर सकता है, जब फसलों पर 65 मिलीमीटर से ज्यादा बेमौसम बरसात की मार पड़ी हो। महाराष्ट्र में जो 30 मिलीमीटर बरसात हुई है, उससे 3 ग्रामीणों की मौत हुई है और 12 जख्मी हुए हैं। 200 घर जमींदोज हुए हैं और लगभग एक सैंकड़ा पालतू जानवर मरे हैं। 7.49 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान हुआ है। लेकिन यह बेमौसम बरसात तय पैमाने से कम हुई है, इसलिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करने से मजबूर है। पैमाने की इस विरोधाभासी आंकड़ेबाजी से रू–ब–रू होने के बावजूद केंद्र सरकार इस मानक पैमाने को बदलने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है जबकि नुकसान का वास्तविक आकलन कर किसानों को हर संभव राहत पहुंचाने की जरूरत है। ❑

मिसाइलों से लैंस होती हमारी सेनाएं

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह अमेरिका की सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक से तीन गुना अधिक तेज है। आईएनएस कोलकाता को गत वर्ष 16 अगस्त को ही नौसेना की स्वीकृति मिल गई थी। यह भारतीय नौसेना का अत्यंत शक्तिशाली व नवीन युद्धपोत है। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रमुख सुधीर मिश्रा ने बताया कि सामान्य तौर पर एक पोत की क्षमता आठ मिसाइलों की होती है लेकिन आईएनएस कोलकाता 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकता है।

■ लक्ष्मी शंकर यादव

रक्षा क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 19 फरवरी को भारतीय वायु सेना को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' से लैस पहला सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान सौंप दिया। बेंगलुरु शहर के येलहांका एयर बेस में आयोजित एयरो इंडिया 2015 एयर शो में यह नई ताकत वाला विमान वायु सेना के हवाले किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैमानिकी महानिदेशक डॉ. के तमिलमणि द्वारा एयरमार्शल एसबीपी सिन्हा को उड़ान मंजूरी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक ए.एम. राजा कन्नू द्वारा एयर मार्शल सुखचैन सिंह को विमान स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस मिसाइल से सुसज्जित होने के बाद यह लड़ाकू विमान शत्रु सेना के लिए अत्यंत घातक एवं विनाशक सिद्ध होने वाला युद्धक विमान बन गया है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर एचएएल के चेयरमैन टी सुवर्णा राजू ने कहा कि एचएएल के लिए यह बेहद गौरव का क्षण है। एचएएल ने अपनी आंतरिक डिजाइन टीम द्वारा गहन विश्लेषण के बाद ब्रह्मोस मिसाइल को इस विमान में लगाया है। एचएएल ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) को कम लागत और स्वदेशी समाधान सेवाएं प्रदान कीं। सुखोई–30 विमान में ब्रह्मोस मिसाइल के संयोजन का सफलतापूर्वक एकीकरण डीआरडीओ, एचएएल और भारतीय वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल व समन्वय को दर्शाता हैं।

उम्मीद है कि बेहद कम समय में दूसरे विमान को भी इस मिसाइल से लैस कर दिया जाएगा। वर्ष 2010 में इस परियोजना को एचएएल ने एक चुनौती के रूप में लिया था क्योंकि उसके पास सुखोई–30 एमकेआई के डिजाइन के संबंध में काफी कम आंकड़े थे। जनवरी 2011 में कंपनी को परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त हुई और एकीकरण संयोजन के लिए बीएपीएल से अनुबंध वर्ष 2014 में हासिल हुआ था। इस तरह काफी कम समय में यह उपलब्धि हासिल हो गई। इससे पहले 14 फरवरी को रक्षामंत्री मनोहर पार्रिकर के समक्ष 290 किलोमीटर की लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस कोलकाता से सफल परीक्षण किया गया था।

ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह अमेरिका की सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक से तीन गुना अधिक तेज है। आईएनएस कोलकाता को गत वर्ष 16 अगस्त को ही नौसेना की स्वीकृति मिल गई थी। यह भारतीय नौसेना का अत्यंत शक्तिशाली व नवीन युद्धपोत है। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रमुख सुधीर मिश्रा ने बताया कि सामान्य तौर पर एक

पोत की क्षमता आठ मिसाइलों की होती है लेकिन आईएनएस कोलकाता 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकता है। इसमें खास तरह के यूनिवर्सल वर्टिकल लांचर डिजाइन का प्रयोग किया गया है जिसकी सहायता से क्षैतिज रूप में इस मिसाइल से किसी भी दिशा में हमला किया जा सकता है।

भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 से ही अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों में शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर रखा है। सन् 2005 में इसे आईएनएस राजपूत में तैनात किया गया था। 21 मार्च 2010 को ओडिशा के तट पर भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस रणवीर से परीक्षण किया गया था। यह लंबवत अर्थात वर्टिकल परीक्षण था। इस मिसाइल को बहुउद्देश्यीय प्लेटफार्म से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस मिसाइल को पहले ही थल सेना में शामिल किया जा चुका है। सेना की दो रेजीमेंटों में यह मिसाइल पूरी तरह से परिचालन में है।

सेना में कार्यात्मक रूप में शामिल ब्रह्मोस के पहले बेड़े में 67 मिसाइलें, पांच मोबाइल ऑटोनॉमस लांर्चस के साथ दो मोबाइल कमांड पोस्ट भी शामिल हैं। सेना ब्रह्मोस ब्लॉक–2 मिसाइलों की दूसरी रेजीमेंट तैयार कर रही है जिसे लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि घनी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रह्मोस ब्लॉक– 2 से आतंकवादी शिविरों समेत बेहद सटीक लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। यह सर्जिकल स्ट्राइक करने में पूरी तरह से सक्षम है। सेना ने अब तीसरी रेजीमेंट में इसकी तैनाती के लिए उत्पादन संबंधी ऑर्डर दिया है।

ब्रह्मोस शब्द भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर बना है। यह मिसाइल सन् 2006 भारत की सैन्य सेवा में है। इसका निर्माण रूस की फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइजेज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा किया गया है। इस श्रेणी की एक मिसाइल की लागत लगभग 13.65 करोड़ रपए है।

भारत भविष्य में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का विकास करेगा और शीघ्र ही विश्व का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास तकरीबन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रहार करने वाली मिसाइल होगी। सितम्बर 2010 में भारत व रूस इसे बनाने को सहमत हुए थे और दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

इसकी अधिकतम गति 2.8 मैक है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना तेज चलने वाली है। लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस ब्रह्मोस मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन की पारंपरिक युद्धक सामग्री अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की लंबाई 8.4 मीटर, व्यास 0.6 मीटर तथा इसका वजन 3000 किलोग्राम है।

ब्रह्मोस के ब्लॉक तीन संस्करण का आधुनिक दिशा निर्देशों और उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ तीन दिसम्बर 2010 को सफल परीक्षण किया गया जिसमें यह मिसाइल परीक्षण के सभी मापदंडों पर अपनी सटीकता सिद्ध करने में सफल रही। इस परीक्षण में विभिन्न बिंदुओं पर इसकी कलाबाजियां सम्मिलित थीं। डीआरडीओ के अनुसार इस सफल परीक्षण के बाद भारत पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके पास इस तरह की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से गोते लगा सकती है तथा कठिन से कठिन लक्ष्यों पर भी सटीक निशाना साध सकती है। इसकी अद्यतन संचालन तकनीक और उन्नत सॉफ्टवेयर ने इसे जमीन और 10 मीटर ऊंचाई तक स्थित लक्ष्य को भेदने में कुशल बना दिया है। इससे सीमा पार के क्षेत्रों में बिना तबाही मचाए आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त किया जा सकता है।

भारत भविष्य में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का विकास करेगा और शीघ्र ही विश्व का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास तकरीबन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रहार करने वाली मिसाइल होगी। सितम्बर 2010 में भारत व रूस इसे बनाने को सहमत हुए थे और दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस नए संस्करण की मारक क्षमता में बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी क्योंकि रूस मिसाइल कंट्रोल रिजीम पर हस्ताक्षर कर चुका है और इसके मुताबिक वह किसी अन्य देश के लिए 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का विकास नहीं कर सकता। यदि यह मिसाइल विकसित हो जाती है तो फिर यह अपना ही रिकार्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइल बन जाएगी। इस मिसाइल का निर्माण सन् 2016 तक कर लिए जाने की उम्मीद है।

स्पष्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइलों की इन सफलताओं से भारत की तीनों सेनाओं की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। ❑

मनरेगा का भ्रष्टाचार पर लगे रोक

यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके जयराम रमेश भी मनरेगा के भ्रष्टाचार से दुखी थे। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका वश चले तो आज ही मनरेगा बंद कर दें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों को इसका वास्तव में लाभ पहुंच रहा है। सवाल है कि थानों में भ्रष्टाचार होता है तो क्या थाने ही बंद कर दिये जाएं, अदालतों में गड़बड़ी होती है तो क्या उन पर ताला लगा दिया जाए। इसी तरह मनरेगा में गड़बड़ी रोकने की भी कोशिश होनी चाहिए। मोदी सरकार से यही उम्मीद है। कितना अच्छा होता कि संसद में यूपीए पर कटाक्ष के साथ ही मोदी बताते कि उनकी सरकार मनरेगा में किस तरह के बदलाव चाहती है।

■ रवि शंकर

संप्रग की गरीबों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को विफलताओं का स्मारक बताने वाली मोदी सरकार ने बजट में इसका पूरा ख्याल रखा है। साल में सौ दिन के काम की गारंटी देने वाली इस योजना के लिए मोदी सरकार ने 34 हजार 699 करोड़ का आवंटन किया है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो यह भी आश्वासन दिया कि अगर सरकार की कमाई बढ़ी तो मनरेगा के लिए पांच हजार करोड़ और दिए जाएंगे।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही संसद में इस योजना पर कटाक्ष किया था। सवाल है कि जिस योजना को प्रधानमंत्री खुद अनुपयोगी मानते हों, उसे इतने भारी–भरकम बजट आवंटन के औचित्य को किस तरह समझा जाए? क्या प्रधानमंत्री मनरेगा की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वह पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी या फिर सरकार में इतना राजनीतिक साहस नहीं रहा कि वह एक गलत योजना को खारिज कर उसकी जगह बेहतर और उपयोगी योजनाओं में यह पैसा लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मनरेगा को 'कांग्रेस पार्टी की विफलता का जीवित प्रमाण' बताया था लेकिन साथ ही आश्वस्त किया कि वह मनरेगा को बंद नहीं करेंगे। क्योंकि इससे कांग्रेस की साठ साल की नाकामी उजागर होती जाएगी। इसी के बाद विपक्ष ने उनके भाषण पर सवाल उठाए।

हालांकि मनरेगा के संबंध में 'गड्ढे खोदे और भरे जाते हैं जैसी टिप्पणी करने वाले मोदी पहले नहीं है। पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे जयराम रमेश ने भी कहा था कि गड्ढे खोदने गड्ढे भरने की जगह कुछ नया होना चाहिए लेकिन वे कुछ कर नहीं सके। यहां मोदी सरकार भी मनरेगा में किस तरह के बदलाव लाना चाहती है, यह साफ नहीं हो सका है। लेकिन, बजट में इसको मिलने वाला पैसा न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि वित्त मंत्री ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता भी बताया। उन्होंने कहा – हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई बेरोजगार न रहे।

बहरहाल, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के मकसद से शुरू की गई मनरेगा यूपीए की फ्लैगशिप योजनाओं में शुमार रही है। भारत के गरीब कामगार तबके की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ने वाले इस योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी मिटाने वाला कानून माना गया है। इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन कुछ हद तक रुका है। खेतीहर मजदूरों के साथ ही सामान्य मजदूरी में भी इजाफा हुआ है।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट की 2014 की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के

कारण भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर कम हुआ है। 2005 में करीब 44 प्रतिशत था जो 2014 में घटकर तीस प्रतिशत रह गया है। लेकिन आज यह योजना संकट में है। शुरुआती सालों में इससे मिलने वाले सकारात्मक परिणामों में अब गिरावट देखी जा रही है। इसके तहत 2006–07 के प्रति व्यक्ति कार्य दिवस 43 दिन की तुलना में साल 2009–10 में प्रति व्यक्ति 54 दिन हो गया लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आई है।

एक तबका ऐसा भी है, जिसे लगता है कि ठीक–ठाक हालात वाले क्षेत्रों में भी मनरेगा के तहत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों ने उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य की तुलना में मनरेगा में अधिक खर्च किया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि इससे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु की बेहतर प्रशासनिक क्षमता भी लक्षित होती है। बहरहाल, इस योजना का खर्च हमेशा से चिंता का कारण रहा है।

वर्ष 2010–11 में मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ से घटकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 33,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को काम दिए जाने के उद्देश्य से यह प्रावधान जोड़ा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत भारी मशीन और महंगी निर्माण सामग्री आदि का इस्तेमाल नहीं हो सकता।

लेकिन यह भी सच है कि मनरेगा में घोटाले होते हैं, गरीबों के फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, हाथों के बजाए मशीनों से काम करवा लिया जाता है, मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है और करीब चार प्रतिशत को ही साल में सौ दिन काम मिल पाता है। ऐसे में जरूरत घोटाले दूर करने की है, फर्जीवाड़ा कम करने की है।

सच पूछें तो यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके जयराम रमेश भी मनरेगा के भ्रष्टाचार से दुखी थे। एक बार उन्होंने कहा था कि उनका वश चले तो आज ही मनरेगा बंद कर दें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों को इसका वास्तव में लाभ पहुंच रहा है। सवाल है कि थानों में भ्रष्टाचार होता है तो क्या थाने ही बंद कर दिये जाएं, अदालतों में गड़बड़ी होती है तो क्या उन पर ताला लगा दिया जाए। इसी तरह मनरेगा में गड़बड़ी रोकने की भी कोशिश होनी चाहिए। मोदी सरकार से यही उम्मीद है। कितना अच्छा होता कि संसद में यूपीए पर कटाक्ष के साथ ही मोदी बताते कि उनकी सरकार मनरेगा में किस तरह के बदलाव चाहती है।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट की 2014 की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के कारण भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर कम हुआ है। 2005 में करीब 44 प्रतिशत था जो 2014 में घटकर तीस प्रतिशत रह गया है। लेकिन आज यह योजना संकट में है। शुरुआती सालों में इससे मिलने वाले सकारात्मक परिणामों में अब गिरावट देखी जा रही है।

यह ठीक है कि इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार अब भी परिवर्तन तो कर सकती है पर सरकार को लगता है कि अगर वह ऐसा कुछ करेगी तो उसे गरीब विरोधी समझ लिया जाएगा। सरकार पर यह आरोप पहले ही लगते रहे हैं कि सारा पैसा कॉरपोरेट के पास जा रहा है। मोदी सरकार को अहसास होना चाहिए कि क्योंकि यह एक्ट है, लिहाजा इसमें बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में संशोधन के लिए भी दो तिहाई सदस्यों की जरूरत पड़ेगी और बदलाव भी ऐसा होना चाहिए जो गरीबों के पक्ष में हों। जिस देश की अधिसंख्य आबादी गरीब हो, वहां यह जरूरी हो जाता है कि गरीबों से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि गरीबों के विकास के लिए बनाई गई लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। चाहे वह मनरेगा हो या इंदिरा आवास योजना। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से इसका फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो इसके हकदार होते हैं या जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अतरू मोदी सरकार से देश के गरीब यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो मनरेगा में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे उनके लिए जारी पैसा उनके पास आ सके।

मनरेगा की दूसरी खामी है कि यह उस योजना से भी खराब है जिसकी नकल के आधार पर यह बनाई गई। महाराष्ट्र में 1970 से एक 'रोजगार गारंटी योजना' चली आ रही थी जो मनरेगा लागू होने के बाद बंद हुई। इसके अंतर्गत हर उस जरूरतमंद को सिर्फ 100 दिन नहीं, सालभर काम देने का प्रावधान था, जो कोई भी सरकार के पास काम मांगने जाता था। पर इसमें एक ही शर्त थी कि इसमें मजदूरी बाजार भाव से कम रखी गई थी। बहरहाल, भारत जैसे गरीब मुल्क में ऐसी योजनाएं वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा देती हैं। इसलिए मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा इसे पारदर्शी बनाना चाहिए। ❑

कालेधन के कारोबार पर लगेगी रोक

अब जबकि काले धन को वापस लाने की बात कहने वाली भाजपा स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में है तो इस टॉस्क फोर्स का महत्व बढ़ जाता है। टॉस्क फोर्स के मुताबिक उभरते हुए राष्ट्र के तौर पर भारत को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छवि भ्रष्ट और बेईमान राष्ट्र की न बने। क्या हम दुनिया के समक्ष नैतिकता का उदाहरण पेश नहीं कर सकते? यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा इस उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करेगी और इस पवित्र एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अन्य तमाम महत्वपूर्ण शक्तियों को भी अपने साथ लेगी।

■ **ए. सूर्यप्रकाश**

वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना विभिन्न समूहों द्वारा की जा रही है। बजट में उठाए गए कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी, बल्कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे आबादी के प्रत्येक हिस्से को लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत नकारात्मक असर डालने वाले काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में जमा किए गए धन को वापस लाए जाने की दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया है।

पहली नजर में ही यह साफ है कि इस बारे में जेटली ने नए विधेयक समेत जो प्रस्ताव दिया है वह निर्णायक और व्यापक है। यह पूर्व की सरकारों द्वारा इस मामले में दिखाए गए ढुलमुल प्रयासों से विपरीत है। पहले की सरकारों ने इस मुद्दे पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और विदेशों में जमा किए गए अवैध धन के खिलाफ लड़ाई के लिए वे केवल बयान देने तक सीमित रहीं।

उदाहरण के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस मुद्दे पर 2012 में जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था वह सरकारी दस्तावेज के बजाय कॉलेज में पढ़ रहे छात्र द्वारा लिखे गए निबंध से अधिक नहीं था। यह तथाकथित श्वेत पत्र लक्ष्यविहीन और दिशाहीन था। यह श्वेत पत्र काले धन के मामले में स्कूली पाठ्य पुस्तक के माध्यम से युवाओं के मन–मस्तिष्क में विचार रोपित करने तक सीमित नजर आया।

यदि हम जेटली के बजट भाषण और तत्कालीन सरकार के श्वेत पत्र की तुलना करें तो पता चलता है कि ऐसे किसी मुद्दे पर किस तरह एक मंत्री और सरकार बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए संप्रग सरकार अपने दस्तावेजों में महज नारों तक सीमित रही। उस समय संप्रग सरकार ने यही कहा कि काले धन के इस बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें सतत् रूप से नैतिक, सामाजिक–आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए नैतिक स्तर पर हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में मूल्यों और नैतिक शिक्षा पर बल देना होगा, विशेषकर कर चोरी और काले धन की

हम सभी जानते हैं कि भारत में काले धन के सृजन में सबसे बड़ा स्रोत रियल इस्टेट बिजनेस है। इसी कारण देश में काले धन की समस्या से निपटने के लिए राजग सरकार ने व्यापक बेनामी ट्रांजैक्शन विधेयक लाने का निर्णय किया है। इससे बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा।

बुराई को मुख्य रूप से प्रचारित–प्रसारित करना होगा। सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सार्वजनिक नीतियों पर जोर देते समय नुकसानदायक उपभोग अथवा खर्च को हतोत्साहित करना होगा और बचत, मितव्ययिता एवं सादगी को प्रोत्साहित करना होगा। इसके साथ ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पाटनी होगी।

संप्रग द्वारा लाए गए श्वेत पत्र में सरकार ने यही कहा कि वह काला धन वापस लाना चाहती है, लेकिन यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे एकतरफा हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ जेटली ने इस बात की घोषणा की कि उनके कर प्रस्तावों में सबसे पहली बात काले धन की समस्या को सुलझाना है और इसके लिए वह प्रभावी और मजबूत कदम उठाने को कृतसंकल्प हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही राजस्व अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड भेजकर ठोस आश्वासन हासिल किया है और इस संदर्भ में विभिन्न मामलों में आयकर विभाग की जांचों में तेजी लाएंगे, बैंक खातों के सही होने की पुष्टि की जाएगी, गैर–बैंकिंग सूचनाएं मुहैया कराई जाएगी और एक समयसीमा में जवाब दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड दोनों देशों के बीच सूचनाओं के स्वतरू आदान–प्रदान के लिए भी अब तैयार है। पूर्व में भारतीय अनुरोध को लेकर स्विस सरकार की अनिच्छा के मद्देनजर यह एक बड़ी उपलब्धि है।

संप्रग सरकार ने अपने दस्तावेज में सुस्ती दिखाते हुए यही कहा था कि विदेशी बैंकों में जमा अघोषित धन स्वदेश भेजने के संदर्भ में मौजूदा कानूनों में सीमित प्रावधान हैं। उसके मुताबिक इस मुद्दे पर बिना अंतरराष्ट्रीय सहमति के विदेशों में जमा धन को देश में लाने के लिए घरेलू कानूनों का क्रियान्वयन बहुत कठिन है। दूसरी तरफ जेटली ने कहा कि सरकार मौजूदा कानूनों की सीमाओं को चिह्नित कर रही है और विदेशों में जमा काले धन को लाने के संदर्भ में सरकार एक व्यापक कानून बनाने पर निर्णय लेगी। संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कर चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत जमा संपत्ति और आय को छिपाने तथा विदेशी परिसंपत्तियों के मामले में कर चोरी का मुकदमा चलाया जा सकेगा और अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान होगा।

इसी तरह आईटीआर दाखिल नहीं करने अथवा विदेशी संपत्ति के बारे में अपर्याप्त जानकारी के लिए 7 वर्ष तक सजा हो सकती है। इस तरह का अपराध चाहे कोई व्यक्ति करे, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान करें, उन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा और वे दंडित होंगे। प्रस्तावित कानून में दो अन्य कठोर प्रावधान भी हैं। आय छिपाने अथवा विदेशी संपत्तिके मामले में कर चोरी को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून 2002 के तहत शामिल किया गया है।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रवर्तन एजेंसियां के हाथ विदेशों में रखे गए अघोषित धन तक पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त इस कानून के तहत आपराधिक कृत्य की परिभाषा में सुधार किया जाएगा ताकि भारत में इसी तरह की संपत्तिको जब्त किया जा सके, क्योंकि विदेशों में बनाई गई संपत्तिको जब्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह फेमा कानून 1999 में भी बदलाव किया जाना है।

हम सभी जानते हैं कि भारत में काले धन के सृजन में सबसे बड़ा स्रोत रियल इस्टेट बिजनेस है। इसी कारण देश में काले धन की समस्या से निपटने के लिए राजग सरकार ने व्यापक बेनामी ट्रांजैक्शन विधेयक लाने का निर्णय किया है। इससे बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आयकर कानून में सुधार किया जा रहा है ताकि अचल संपत्ति की खरीद के मामले में 20,000 या उससे अधिक की राशि नकद न ली जा सके। चार वर्ष पहले भाजपा ने काले धन पर एक टॉस्क फोर्स गठित किया था, जिसमें सदस्य के तौर पर एस. गुरुमूर्ति समेत कई जाने–माने लोग शामिल थे। इस समूह ने व्यापक कानूनी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश की थी, लेकिन संप्रग ने संकीर्ण कारणों से इन पर ध्यान नहीं दिया।

अब जबकि काले धन को वापस लाने की बात कहने वाली भाजपा स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में है तो इस टॉस्क फोर्स का महत्व बढ़ जाता है। टॉस्क फोर्स के मुताबिक उभरते हुए राष्ट्र के तौर पर भारत को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छवि भ्रष्ट और बेईमान राष्ट्र की न बने। क्या हम दुनिया के समक्ष नैतिकता का उदाहरण पेश नहीं कर सकते? यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा इस उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करेगी और इस पवित्र एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अन्य तमाम महत्वपूर्ण शक्तियों को भी अपने साथ लेगी। अब यह विपक्ष पर है कि वह संसद में सरकार के इस कदम का समर्थन करे ताकि वर्तमान बजट सत्र में इन प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया जा सके। ❑

फिर वही जोखिम

मोदी ने यह अप्रत्याशित कदम एक ऐसे समय उठाया है जब भारत के संदर्भ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने प्रतिकूल बयान दिया है। पाकिस्तान के साथ वार्ता की बहाली मोदी की तरफ से एक बड़ी भूल है और यहां तक कि इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नई शांति वार्ता के बहाने भारत के खिलाफ नए आतंकी हमलों को शुरू करने का अवसर मिलेगा। यह देखा गया है कि हर बार जब भी भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की उतनी बार उसे नियंत्रण रेखा अथवा देश के आंतरिक हिस्सों में नए हमलों का सामना करना पड़ा है।

■ ब्रह्मा चेलानी

परमाणु दुर्घटना पर जवाबदेही और समानांतर निगरानी (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ–साथ) के मुद्दे पर अमेरिका से छूट हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान से वार्ता की शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसके पक्ष में हैं। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तरीय वार्ता का निर्णय सार्क की आड़ में लिया गया है। यहां इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता कि मोदी पाकिस्तान के साथ बिना किसी शर्त के वार्ता करने को तैयार हुए हैं जिसका मतलब है कि भारत को किसी भी मुद्दे पर अपनी चिंताओं से राहत नहीं मिलने वाली है। सेना प्रमुख के रूप में जनरल दलबीर सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण के केंद्र अभी भी बरकरार हैं। इस क्रम में जम्मू और कश्मीर में नए आतंकी हमले पाकिस्तान की निराशा को जताते हैं।

मोदी ने यह अप्रत्याशित कदम एक ऐसे समय उठाया है जब भारत के संदर्भ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने प्रतिकूल बयान दिया है। पाकिस्तान के साथ वार्ता की बहाली मोदी की तरफ से एक बड़ी भूल है और यहां तक कि इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नई शांति वार्ता के बहाने भारत के खिलाफ नए आतंकी हमलों को शुरू करने का अवसर मिलेगा। यह देखा गया है कि हर बार जब भी भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की उतनी बार उसे नियंत्रण रेखा अथवा देश के आंतरिक हिस्सों में नए हमलों का सामना करना पड़ा है।

अतीत के उदाहरणों से साफ पता चलता है कि वार्ता बहाली की तकरीबन सभी कोशिशें शुभ नहीं रही हैं। इस बार पहले ओबामा ने नवाज शरीफ को फोन किया और महज कुछ घंटों बाद ही मोदी ने शरीफ को फोन किया और शांति प्रक्रिया की बहाली की बातें कीं। अब आगे क्या होने जा रहा है? भारत के खिलाफ एक और आतंकी हमला?

पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करने के लिए आखिर क्यों मोदी सरकार सार्क देशों के दौरे पर विदेश सचिव को भेजने जा रही है? क्या सरकार यह सोचती है कि इस तरह से भारतीय जनता से चीजों को छुपाया जा सकेगा? नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मोदी के साथ अपनी प्रसिद्ध चाय पर चर्चा के दौरान ओबामा जिस एक मुद्दे बात पर सर्वाधिक केंद्रित रहे वह था पाकिस्तान। उन्होंने बताया भी कि उनके विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस वर्ष की शुरुआत में गांधीनगर में संपन्न हुए वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में मोदी के साथ हुई अपनी चर्चा के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी थी।

ओबामा मोदी से यही जानना चाहते थे कि आखिर क्यों मोदी ने केरी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि भारत

पाकिस्तान के साथ वार्ता को शुरू करे। पाकिस्तान को उदार अनुदान देने की अमेरिकी नीति पर सवाल उठाने और भारत के खिलाफ उसके प्रतिकूल रुख का मुद्दा उठाने के बजाय मोदी ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई और ओबामा को यही बताया कि पेशावर नरसंहार के बाद वह पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे लगातार युद्धविराम उल्लंघन और आतंकवादी जकी–उर–रहमान लखवी को जेल से रिहा किए जाने के प्रयासों के चलते वह ऐसा नहीं करने को विवश हुए।

मोदी के मुताबिक बावजूद इसके उन्होंने मित्रता के संकेत दिए और पेशावर हमले में मारे गए लोगों के प्रति भारतीय स्कूलों में दो मिनट का मौन रखने को कहा गया। ओबामा ने अकेले में मोदी से जिस बात का आग्रह किया उसे भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने सार्वजनिक किया है। वाशिंगटन में एक समय परमाणु लॉबिंग में शामिल रहे रिचर्ड वर्मा ने मुंबई में कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए सतत रूप से काम करता रहेगा।

वास्तविकता भी यही है कि भारत से वापस लौटने के बाद ओबामा ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक अरब डॉलर से अधिक की नई मदद राशि देने का प्रस्ताव किया और चीनी राष्ट्रपति को अमेरिकी आने का न्योता दिया। 2001 से अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रति वर्ष आर्थिक मदद के तौर पर अरबों डॉलर दिए हैं। बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान को यह समझा पाने में विफल रहा है कि वह सरकार समर्थित आतंकी ढांचे को नष्ट करे।

पाक सेना अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी छद्म युद्ध को तेज करने और परमाणु हथियारों के विस्तार के लिए करती है। अभी भी मोदी सरकार ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की नई मदद का विरोध नहीं किया है।

उसने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के निर्माण से रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की।

पाक सेना अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी छद्म युद्ध को तेज करने और परमाणु हथियारों के विस्तार के लिए करती है। अभी भी मोदी सरकार ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की नई मदद का विरोध नहीं किया है। भारत और अमेरिका के लिए यह एक आसान बात थी कि वे अपनी साझा चिंताओं पर संयुक्त बयान जारी करते, जैसा कि ओबामा यात्रा के दौरान हुआ। कुछ ठोस कदम के माध्यम से ही अमेरिकी गंभीरता का पता चलता, जैसे कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहीम को जेल में डाले जाने की बात की जाती। फिलहाल अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद से पुरस्कृत कर रहा है और भारत के खिलाफ उसे हथियार दे रहा है।

यह अच्छी बात है कि अमेरिका और भारत अपने संयुक्त एशिया–प्रशांत सामरिक विजन दस्तावेज के माध्यम से चीन को चेतावनी देते हैं, लेकिन यह भारत के लिए किस तरह मददगार साबित होगा जब अमेरिका चीन–भारत विवादों में तटस्थ बना रहेगा। इस पृष्ठभूमि में यह परेशान करने वाली बात है कि मोदी अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार हुए हैं। वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन कोई शांति नहीं आई।

ताजा वार्ता प्रक्रिया भी पूर्व की पाक नीतियों को शायद ही बदल सकें। बहरहाल स्थिति यही है कि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान भारत के प्रति अपनी इस मूल धारणा से बंधा हुआ है कि वह भारत की प्रगति को हर हाल में और हरसंभव तरीके से रोकेगा फिर वह चाहे सही तरीके से हो अथवा गलत। उसके लिए आतंकवाद एक उपयोगी हथियार है। पेशावर नरसंहार से बुरी तरह हिलने के बाद भी पाक का आतंकी संगठनों के साथ मधुर रिश्ता बरकरार है। कुल मिलाकर कोई भी देश उसकी इस सामरिक सोच और दृष्टिकोण को बदल नहीं रहा है कि वह अपने आतंकी ढांचे को खत्म करे। इस क्रम में दूसरा अनुत्तरित सवाल यही है कि आखिर मोदी ऐसी स्थिति में वार्ता क्यों शुरू कर रहे हैं जब शरीफ सरकार बहुत ही कमजोर है और सेना पर निर्भर है। शरीफ भारत के साथ वास्तविक घनिष्ठता कायम करने की स्थिति में नहीं हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी मनमोहन सिंह से उत्तराधिकार में मिलीं पाकिस्तान के प्रति टूटी–बिखरी नीतियों को अभी तक सही नहीं कर सके हैं। मनमोहन सिंह ने अपने शासनकाल के 10 वर्षों में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की अतार्किक नीति का अनुसरण किया था। ❑

संचार का तरीका बदलती तकनीक

सिस्को के अनुसार वर्ष 2016 में दुनिया भर में दस अरब मोबाइल फोन काम कर रहे होंगे। गूगल के एक सर्वे के मुताबिक, भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद फिलहाल अमेरिका के 24.5 करोड़ स्मार्टफोन धारकों के आधे से भी कम है, पर उम्मीद है कि 2016 तक मोबाइल फोन इंटरनेट तक पहुंचने का बड़ा जरिया बनेंगे और 350 करोड़ संभावित इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में से आधे से ज्यादा मोबाइल के जरिये ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और निश्चय ही तब छायाचित्र संचार का दायर और बढ़ जाएगा।

■ मुकुल श्रीवास्तव

इसमें कोई शक नहीं कि मानव सभ्यता के इतिहास को बदलने में सबसे बड़ा योगदान आग और पहिये के आविष्कार ने दिया। लेकिन यह भी सच है कि इंटरनेट की अवधारणा ने इस सभ्यता का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। यह समय का एक चक्र पूरा हो जाने जैसा है।

इंसान ने संचार के लिए सबसे पहले चित्रों का सहारा लिया था, जिनके साक्ष्य आदिकालीन गुफाओं में देखे जा सकते हैं। फिर भाषा और लिपि का विकास हुआ और सभ्यता लगातार आगे बढ़ती रही। संवाद के लिए भाषा पर ज्यादा निर्भरता रही। पर इंटरनेट के आगमन और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बढ़ते चलन ने संचार के उस युग को दुबारा जीवित कर दिया जो सभ्यता की शुरु आत में हमारा साथी था। संवाद के लिए तस्वीरें और स्माइली का प्रयोग अब ज्यादा बढ़ रहा है। स्माइली ऐसे चिह्न हैं जिनसे भाव प्रेषित किए जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा 20 से 29 वर्ष के युवा वर्ग से आता है।

इसमें खास बात यह है कि यह युवा वर्ग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। जल्दी ही वह वक्त इतिहास हो जाने वाला है जब आपको कोई एसएमएस मिलेगा कि क्या हो रहा है और आप लिखकर जवाब देंगे। अब समय दृश्य संचार का है। आप तुरंत एक तस्वीर खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे और पूछने वाले को भेज देंगे या एक स्माइली भेज देंगे। यानी आपको कुछ कहने या लिखने की जरूरत नहीं, कहने का काम अब तस्वीरें करेंगी।

फोटो या छायाचित्र बहुत पहले से संचार का माध्यम रहे हैं, पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट के साथ ने इन्हें इंस्टेंट कम्युनिकेशन मोड (त्वरित संचार माध्यम) में बदल दिया है। अब महज शब्द नहीं, भाव और परिवेश भी बोल रहे हैं। वह भी तस्वीरों और स्माइली के सहारे। इस संचार को समझने के लिए न तो किसी भाषा विशेष को जानने की अनिवार्यता है और न ही वर्तनी और व्याकरण की बंदिशें। तस्वीरें पूरी दुनिया की एक सार्वभौमिक भाषा बनकर उभर रही हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पा रहा है। एसी नील्सन के नियंत्रण मीडिया खपत सूचकांक 2012 से पता चलता है कि एशिया (जापान को छोड़कर) और ब्रिक देशों में इंटरनेट मोबाइल फोन पर टीवी व वीडियो देखने की आदत पश्चिमी देशों व यूरोप के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल पर लिखित एसएमएस संदेशों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है।

तकनीक के इस डिजीटल युग में हम अब भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत समस्याओं के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा, तस्वीर उतनी चमकीली भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तस्वीरों और स्माइली पर बढ़ती निर्भरता संचार के लिए दुनिया भर की भाषाओं के लिए खतरा भी हो सकती है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

वायरलेस उद्योग की अंतरराष्ट्रीय संस्था सीटीआईए की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में 2.19 ट्रिलियन एसएमएस संदेशों का आदान–प्रदान पूरी दुनिया में हुआ, जो 2011 की तुलना में भेजे गए संदेशों की संख्या से पांच प्रतिशत कम रहा। वहीं मल्टीमीडिया मेसेज (एमएमएस) जिसमें फोटो और वीडियो शामिल हैं, की संख्या साल 2012 में 41 प्रतिशत बढ़कर 74.5 बिलियन हो गई। एक साधारण तस्वीर से संचार, शब्दों और चिह्नों के मुकाबले कहीं आसान है।

उन्नत होती तकनीक और बढ़ते स्मार्टफोन के प्रचलन ने फोटोग्राफी को अतीत की स्मृतियों को सहेजने की कला से आगे बढ़ाकर एक त्वरित संचार माध्यम में तब्दील कर दिया है। फोन पर इंटरनेट

और नए–नए एप्स लगातार संचार के तरीकों को बदल रहे हैं। स्नैप चैट एक ऐसा ही मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्रयोगकर्ता को वीडियो और फोटो भेजने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें फोटो–वीडियो देखे जाने के बाद अपने आप हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। स्नैप चैट के प्रयोगकर्ता प्रतिदिन 200 मिलियन चित्रों का आदान–प्रदान कर रहे हैं।

फेसबुक पर लोग प्रतिदिन 300 मिलियन चित्रों का आदान–प्रदान कर रहे हैं और साल भर में यह आंकड़ा 100 बिलियन का है। चित्रों का आदान–प्रदान करने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताओं की है जो स्मार्टफोन द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं और यह चीज संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। तथ्य यह भी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बढ़ते इस्तेमाल में संचार के पारंपरिक तरीके, जिसका आधार भाषा हुआ करती थी, वह कुछ निश्चित चिह्नों/प्रतीकों में बदल रही है। इसे हम इमोजीस या फिर इमोटिकॉन के रूप में जानते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं। सन् 1982 में अमेरिकी कंप्यूटर विज्ञानी स्कॉट फॉलमैन ने इसका आविष्कार किया था।

स्कॉट फॉलमैन ने जब इसका आविष्कार किया था, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये चित्र प्रतीक मानव संचार में इतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। व्हाट्सएप, हाइक के अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल संचार के लिए हो रहा है। सिर्फ एप्पल के आईफोन में ही दो करोड़ बार इमोजी डाउनलोड

फेसबुक पर लोग प्रतिदिन 300 मिलियन चित्रों का आदान–प्रदान कर रहे हैं और साल भर में यह आंकड़ा 100 बिलियन का है। चित्रों का आदान–प्रदान करने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताओं की है जो स्मार्टफोन द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं और यह चीज संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है।

किए गए हैं। बहुत से स्मार्टफोनों में सात सौ बीस से ज्यादा स्माइली आइकन मौजूद हैं। स्मार्टफोन या फिर चैट एप में पारंपरिक स्माइली वाले चेहरे से लेकर दैत्य रूपी या फिर चुलबुले चेहरे वाले आइकन मौजूद हैं। मोबाइल अब एक आवश्यक आवश्यकता बन कर हमेशा हमारे साथ रहता है।

सिस्को के अनुसार वर्ष 2016 में दुनिया भर में दस अरब मोबाइल फोन काम कर रहे होंगे। गूगल के एक सर्वे के मुताबिक, भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद फिलहाल अमेरिका के 24.5 करोड़ स्मार्टफोन धारकों के आधे से भी कम है, पर उम्मीद है कि 2016 तक मोबाइल फोन इंटरनेट तक

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दस वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 0.4 प्रतिशत परिवारों को ही घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की ग्रामीण जनसंख्या का दो प्रतिशत ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है।

पहुंचने का बड़ा जरिया बनेंगे और 350 करोड़ संभावित इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में से आधे से ज्यादा मोबाइल के जरिये ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और निश्चय ही तब छायाचित्र संचार का दायर और बढ़ जाएगा।

हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी उन्नति के रथ पर सवार तस्वीरें आने वाले वक्त में मानव संचार की दुनिया बदल देंगी, पर तस्वीर पूरी रंगीन हो ऐसा भी नहीं है। छायाचित्र संचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में डिजीटल डिवाइड बढ़ रहा है।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दस वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 0.4 प्रतिशत परिवारों को ही घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की ग्रामीण जनसंख्या का दो प्रतिशत ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है।

यह आंकड़ा इस हिसाब से बहुत कम है क्योंकि इस वक्त ग्रामीण इलाकों के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से अट्ठारह प्रतिशत को इसके इस्तेमाल के लिए दस किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। तकनीक के इस डिजीटल युग में हम अब भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत समस्याओं के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा, तस्वीर उतनी चमकीली भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तस्वीरों और स्माइली पर बढ़ती निर्भरता संचार के लिए दुनिया भर की भाषाओं के लिए खतरा भी हो सकती है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ❑

परमाणु बिजली घरों का कचरा है बड़ी समस्या

बुंदेलखंड के ललितपुर व छतरपुर जिले में यूरेनियम अयस्क भारी मात्रा में पाया गया है। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना के भूगर्भ में आयोडीन का आधिक्य है। दोनों तत्व अणु विकिरण के अच्छे वाहक है। यह इलाका भयंकर गर्मी वाला है जहां 47 डिग्री तापमान कई–कई दिनों तक होता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव विकिरण फूटा तो तेजी से फैलेगा। यहां केन– बेतवा नदी जोड़ भी भू संरचना को प्रभावित करेगी।

■ **पंकज चतुर्वेदी**

हाल में परमाणु जवाबदेही कानून के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई दुर्घटना होने की सूरत में पीड़ित पक्ष रियेक्टर सप्लाई करने वाली कपंनी पर मुआवजे का दावा नहीं कर सकेगा। सालों साल बिजली की मांग बढ़ रही है, हालांकि अभी हम कुल 4780 मेगावाट बिजली ही परमाणु से उपजा रहे हैं जो हमारे कुल बिजली उत्पादन का महज तीन प्रतिशत है।

एक अनुमान है कि हमारे परमाणु ऊर्जाघर 2020 तक 14600 मेगावाट बिजली बनाने लगेंगे और 2050 तक हमारे कुल उत्पादन का एक–चौथाई अणु–शक्ति से आएगा। विकास का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण बिजली की मांग व उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक है। इस रूप में परमाणु बिजली जरूरी विकल्प है लेकिन परमाणुघरों से निकले कचरे का निबटान कहां व कैसे हो इस पर गंभीरता से सोचना होगा। सनद रहे कि एक सीमा से अधिक विकिरण मानव शरीर व पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह होता है और सालों–साल प्रभावी रहता है। उसकी नजीर जापान के हिरोशिमा व नागासाकी हैं।

खैर, परमाणु जवाबदेही पर नए स्पष्टीकरण के बाद यह मसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो इस मसले पर 14 मार्च 2012 को एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा में बताया था कि परमाणु कचरे का निबटना कैसे होता है। लेकिन कहां और कब होता है, जैसे बेहद संवेदनशील सवाल अनुत्तरित ही रहते हैं। यह बात सालों पहले भी सुगबुगाई थी कि ऐसे कचरे को जमीन के भीतर गाड़ने के लिए उपेक्षित, वीरान व पथरीले इलाकों को चुना गया है और उसमें बुंदेलखंड का भी नाम था।

सरकार का लोकसभा में दिया गया जवाब बताता है कि परमाणु बिजलीघर के कचरे को अतिसंवेदनशील, कम संवेदनशील व निष्क्रिय में छांटा जाता है। खतरनाक कचरे को सीमेंट, पॉलीमर, कांच जैसे पदार्थों में मिला ठोस में बदला जाता है। इसे दोहरी परत वाले स्टेनलेस स्टील के पात्रों में तब तक बिजली घरों में ही रखा जाता है। पूरी तरह ठोस में बदल जाने के बाद जब उसके रेडियो एक्टिव गुण क्षीण हो जाते हैं तो उसे जमीन की गहराई में दफनाने की तैयारी की जाती है। पश्चिमी देश ऐसे कचरे को अब तक गहरे समुद्र में दबाते रहे हैं। अणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यूरेनियम नाम के रेडियो एक्टिव को बतौर ईधन प्रयोग में लाया जाता है।

न्यूट्रान की बम वष पर रेडियो एक्टिव तत्व में भयंकर विखंडन होता है। विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उसमें केडमियाम या बोरोन स्टील की छड़ें लगाई जाती है। इसके नाभिकीय विखंडन पर ऊर्जा के साथ– साथ क्रिप्टान, जिनान, सीजियम, स्ट्रांशियम आदि तत्व बनते जाते हैं। एक बार विखंडन शुरू होने पर यह

प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती हैं। इस तरह यहां से निकला कचरा बेहद विध्वंसकारी होता है और इसका निबटान सारी दुनिया के लिए समस्या है।

भारत में हर साल भारी मात्रा में निकलने वाले ऐसे कचरे को हिमालय पर्वत, गंगा–सिंधु के कछार या रेगिस्तान में तो डाला नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं भूकंप की आशंका है तो कही बाढ़ का खतरा। कहीं भूजल स्तर काफी ऊंचा है तो कहीं घनी आबादी। यह पुख्ता खबर है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों को बुंदेलखंड, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का कुछ पथरीला इलाका इस कचरे को दफनाने के लिए सर्वाधिक मुफीद लगा और अब तक कई बार यहां गहराई में स्टील के ड्रम दबाए जा चुके हैं। परमाणु कचरे को बुंदेलखंड में दबाने का सबसे बड़ा कारण यहां यहां 50 फीट गहराई तक ही मिट्टी है और उसके बाद 250 फीट गहराई तक ग्रेनाईट पत्थर है।

भूगर्भ वैज्ञानिक अविनाश खरे बताते हैं कि बुंदेलखंड ग्रेनाइट का निर्माण कोई 250 करोड़ साल पहले तरल मेग्मा से हुआ था। तबसे विभिन्न मौसमों के प्रभाव ने इस पत्थर को अन्य किसी प्रभाव का रोधी बना दिया है। यहां गहराई में बगैर किसी टूट या दरार के चट्टाने हैं और इसीलिए इसे कचरा दबाने का सुरक्षित स्थान मना गया। अणु कचरे से निकलने वाली किरणों न तो दिखती हैं और न ही इसका कोई स्वाद या गंध होता है। लेकिन ये मानव शरीर के प्रोटीन, एंजाइम, अनुवांशिक अवयवों में बदलाव ला देती हैं।

यदि एक बार रेडियो एक्टिव तत्व शरीर में मात्रा से अधिक प्रवेश कर जाए तो उसके दुष्प्रभाव से बचना असंभव है। विभिन्न अणु बिजली घरों के करीबी गांव–बस्तियों के बाशिंदों में शरीर में गांठ बनना, गर्भपात, कैंसर, अविकसित बच्चे पैदा होना जैसे हादसे आम हैं क्योंकि जैव कोशिकाओं पर रेडियो एक्टिव असर पड़ते ही उनका विकृत होना शुरू हो जाता है। खून के प्रतिरोधी तत्व भी विकिरण के चलते कमजोर हो जाते हैं। इससे एलर्जी, दिल की बीमारी, डायबीटिज जैसे रोग होते हैं। पानी में विकिरण रिसाव की दशा में नाईट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। यह जानलेवा होता है।

इस कचरे को बुंदेलखंड में ठिकाने लगाने से पहले वैज्ञानिकों ने यहां बाढ़, भूकंप, युद्ध और जनता की भूजल पर निर्भरता जैसे मसलों पर शायद गंभीरता से विचार नहीं किया। इलाके में पांच साल में दो बार कम वर्ष व एक बार अति वर्ष के कारण बाढ़ मौसमी चक्र बन चुका है। श्री खरे बताते हैं कि बुंदेलखंड का जल–स्तर शून्य से सौ फीट तक है। बुंदेलखंड ग्रेनाइट में बेसीन, सब बेसीन और माईक्रो बेसीन, यहां नदियों, नालों के बहाव के आधार पर बंटे हुए हैं लेकिन ये किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं यानी पानी के माध्यम से यदि रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया तो उसे रोक पाना संभव नहीं होगा। नदियों के प्रभाव से पैदा टैटोनिक फोर्स के कारण चट्टानों में ज्वाईंट प्लेन, लीनियामेंट टूटफूट होती रहती है, जिससे विकिरण फैलने की संभावना बनी रहती है।

बुंदेलखंड के ललितपुर व छतरपुर जिले में यूरेनियम अयस्क भारी मात्रा में पाया गया है। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना के भूगर्भ में आयोडीन का आधिक्य है। दोनों तत्व अणु विकिरण के अच्छे वाहक है। यह इलाका भयंकर गर्मी वाला है जहां 47 डिग्री तापमान कई–कई दिनों तक होता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव विकिरण फूटा तो तेजी से फैलेगा। यहां केन– बेतवा नदी जोड़ भी भू संरचना को प्रभावित करेगी। हालांकि परमाणु ऊर्जा विभाग विकिरण को खतरनाक नहीं मानता है। विभाग के एक परिपत्र के मुताबिक विकिरण सदैव पर्यावरण का हिस्सा रहा है। अंतरिक्ष किरणों, मिट्टी, ईंट, कंक्रीट के घरों आदि में 15 से 100 मिलीरिम सालाना का विकिरण उत्सर्जित होता है पर परमाणु भट्टी से निकलने वाले कचरे का विकिरण इससे कई–कई हजार गुणा होता है। भले ही भूविज्ञान परमाणु कचरे के निबटान के लिए बुंदेलखंड को माकूल मानते हों, लेकिन वास्तव में यहां की जनता की अल्प जागरूकता और जन प्रतिनिधियों के उपेक्षित रवैये के कारण ही यह सबसे कम प्रतिरोध वाला इलाका मान लिया गया है। ❑

एक अनुमान है कि हमारे परमाणु ऊर्जाघर 2020 तक 14600 मेगावाट बिजली बनाने लगेंगे और 2050 तक हमारे कुल उत्पादन का एक–चौथाई अणु–शक्ति से आएगा। विकास का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण बिजली की मांग व उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक है। इस रूप में परमाणु बिजली जरूरी विकल्प है लेकिन परमाणुघरों से निकले कचरे का निबटान कहां व कैसे हो इस पर गंभीरता से सोचना होगा।

पाकिस्तान में निशाने पर अल्पसंख्यक

अभी चंद रोज पहले ही आतंकियों ने सिंध प्रांत में जुमे की नमाज की दौरान शिया मस्जिद में ही हमलाकर पांच दर्जन से अधिक लोगों की जान ली। यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने शिया समुदाय को निशाने पर लिया हो। सच तो यह है कि पाकिस्तान में शिया भी उतने ही असुरक्षित और भयग्रस्त हैं जितने कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय। पाकिस्तान में शिया ही नहीं ईसाई, हिंदू व सिख समुदाय भी असुरक्षित हैं।

■ **अरविन्द जयतिलक**

पाकिस्तान के पेशावर में तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों ने शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमलाकर एक बार फिर अपने कायराना कृत्य को अंजाम दिया है। इस हमले में दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने यह बर्बर कृत्य उस समय किया जब लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले ने फिर साबित किया है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय समेत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। वे लगातार आतंकियों और कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं।

अभी चंद रोज पहले ही आतंकियों ने सिंध प्रांत में जुमे की नमाज की दौरान शिया मस्जिद में ही हमलाकर पांच दर्जन से अधिक लोगों की जान ली। यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने शिया समुदाय को निशाने पर लिया हो। सच तो यह है कि पाकिस्तान में शिया भी उतने ही असुरक्षित और भयग्रस्त हैं जितने कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय। पाकिस्तान में शिया ही नहीं ईसाई, हिंदू व सिख समुदाय भी असुरक्षित हैं। चंद माह पहले आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चर्च व्हाइट–स्टोन ऑल सेंट को निशाना बना सैकड़ों की जान ली थी। हमले की जिम्मेदारी तहरीक–ए–तालिबान के धड़े जनदुल्ला ने ली और कहा कि यह हमला अमेरिकी ड्रोन हमलों का बदला है और वे तब तक गैर–मुस्लिमों को निशाना बनाते रहेंगे जब तक कि अमेरिकी ड्रोन हमले बंद नहीं होते हैं। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या 1.6 प्रतिशत है और दिनों–दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक, आतंकियों का डर और दूसरा उनका जबरन धर्मातरण। धर्मातरण का विरोध करने पर उनके साथ बर्बरता की जाती है। अभी दो वर्ष पहले ही पाकिस्तान के गोजरा में 1000 कट्टरपंथियों ने ईसाई घरों पर हमला बोल छह लोगों को जिंदा जला दिया। इस तरह की बर्बर घटनाएं पाकिस्तान में आम हैं।

पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक मुख्य कारण इस्लामिक विचारधारा का उग्र प्रसार भी है। उसी का कुपरिणाम है कि आज पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा है। बेहतर होगा कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करे। उसे समझना होगा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से उसकी छवि बिगड़ रही है।

अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के लिए सिर्फ आतंकी समूह ही नहीं बल्कि

सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां, विशेषकर ईशनिंदा कानून भी जिम्मेदार है। कहीं आतंकी नाराज न हो जाएं इस भय से सरकार इस कानून को नहीं हटा रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को हाशिए पर डाल दिया है। गत वर्ष अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तानी स्कूलों की किताबें अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। मजहबी शिक्षक धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस्लाम के शत्रु की तरह पेश करते हैं। उन्हें काफिर बता मुस्लिम बच्चों के मन में जहर घोलते हैं।

रिपोर्ट में यह भी उद्घाटित हुआ कि पाकिस्तान में सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भारत और ब्रिटेन के संबंध में नकारात्मक टिप्पणियों से अटी पड़ी हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों के इस्लामीकरण की शुरुआत अमेरिका समर्थित तानाशाह जिया–उल–हक के काल में हुई। बाद की सरकारों ने पाठ्यक्रमों में सुधार की बात तो की लेकिन उसमें तब्दीली की हिम्मत नहीं दिखा सकीं। दरअसल वे मजहबी कट्टरपंथियों और आतंकियों से डरती रही हैं। पाकिस्तानी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के शब्द उड़ेले गए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान का आम जनमानस गैर–इस्लामिक देशों और वहां के निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखता है तो अचरज नहीं है।

गत वर्ष अमेरिकी संगठन प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तान में हर चार में से तीन नागरिक भारत समेत गैर–इस्लामिक देशों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसका मुख्य कारण स्कूलों में परोसी जा रही जहरीली मजहबी शिक्षा है। एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक 57 प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिक भारत और अमेरिका को अलकायदा और तालिबान से भी खतरनाक मानते हैं। उल्लेखनीय यह भी कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करने वाले और भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। वे आतंकी और कट्टरपंथी समूहों के निशाने पर हैं।

अभी गत वर्ष आतंकियों ने पाकिस्तान के 42 वर्षीय मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी कि उन्होंने अल्पसंख्यक हितों की आवाज बुलंद की। वे चाहते थे कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी उनका वाजिब हक मिले और सरकार ईशनिंदा कानून में बदलाव लाए। लेकिन कट्टरपंथियों को उनकी पहल रास नहीं आई और वे उनकी जान लेकर ही माने।

कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाने वाले पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर भी कट्टरपंथियों की क्रूरता से बच नहीं पाए। उनकी हत्या की विश्वव्यापी आलोचना हुई और पाकिस्तान को अपना बचाव करते हुए कहना पड़ा कि वह दहशतगर्दी से कड़ाई से निपटेगा। लेकिन सच्चाई है कि इस दिशा में उसने आज तक कुछ भी प्रयास नहीं किया। उल्टे वह दहशतगर्दों को संरक्षण ही दे रहा है।

नतीजा यह है कि आज कट्टरपंथियों का हौसला बुलंद है और वे उदारवादी सोच रखने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली आसिया बीबी को भी कट्टरपंथियों ने मार डाला। भला ऐसे हालात में कोई अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में रहना क्यों चाहेगा? दुर्भाग्यपूर्ण यह भी कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों के पलायन को लेकर तनिक

रिपोर्ट में कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों के इस्लामीकरण की शुरुआत अमेरिका समर्थित तानाशाह जिया–उल–हक के काल में हुई। बाद की सरकारों ने पाठ्यक्रमों में सुधार की बात तो की लेकिन उसमें तब्दीली की हिम्मत नहीं दिखा सकीं। दरअसल वे मजहबी कट्टरपंथियों और आतंकियों से डरती रही हैं। पाकिस्तानी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के शब्द उड़ेले गए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान का आम जनमानस गैर–इस्लामिक देशों और वहां के निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखता है तो अचरज नहीं है।

गौरतलब यह कि पाकिस्तान निर्माण के समय वहां हिंदुओं की आबादी तकरीबन 15 प्रतिशत थी। लेकिन आज वे एक फीसद से भी कम रह गए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी ताकतें दो रास्ते अपना रही हैं। एक, उनकी हत्या की जा रही है और दूसरा उनका जबरन धर्मांतरण हो रहा है। नतीजतन वे पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हैं।

भी फिक्रमंद नहीं है। नतीजा आतंकियों और कट्टरपंथियों का हौसला बुलंद है।

गौरतलब यह कि पाकिस्तान निर्माण के समय वहां हिंदुओं की आबादी तकरीबन 15 प्रतिशत थी। लेकिन आज वे एक फीसद से भी कम रह गए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी ताकतें दो रास्ते अपना रही हैं। एक, उनकी हत्या की जा रही है और दूसरा उनका जबरन धर्मातरण हो रहा है। नतीजतन वे पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से कट्टरपंथियों और तालिबानी दहशतगदरे पर कड़ी कार्रवाई न करने का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान रोजाना धमाकों की गूंज के बाद लाशें गिन रहा है। इसके लिए वहां की हुकूमत ही जिम्मेदार है। दुनिया पाकिस्तान को लगातार आगाह कर रही है कि वह अपनी धरती पर कट्टरपंथियों और तालिबानियों को संरक्षण न दे, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं। हकीकत तो यह है कि जब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर मिलता है, इसका लाभ उठाने के बजाय वे कट्टरपंथी दहशतगदरे के पांव सहलाते हैं। ऐसी स्थिति में कट्टरपंथ का बोलबाला क्यों नहीं बढ़ेगा?

पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक मुख्य कारण इस्लामिक विचारधारा का उग्र प्रसार भी है। उसी का कुपरिणाम है कि आज पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा है। बेहतर होगा कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करे। उसे समझना होगा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से उसकी छवि बिगड़ रही है। दुनिया में संदेश जा रहा है कि पाक सरकार दहशतगर्दों के साथ है। अगर पाकिस्तान को विश्व बिरादरी में सम्मान हासिल करना है तो उसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और कट्टरपंथियों के फन को कुचलना होगा। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

आखिर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा क्यों

दुनिया के सबसे समृद्ध बीस देशों में से केवल चार देश ही ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है। तब कैसे माना जाए भला कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है? कितना दुर्भाग्य है कि भारत में आज अंग्रेजी इतनी जरूरी भाषा बन गई कि हर पढ़–लिखे को अपनी पढ़ाई–लिखाई अधूरी लगने लगती है, यदि वह अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है तो। उसे लगता है अपनी भाषा आए या न आए अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। अंग्रेजी का न आना उसके भीतर एक हीनताबोध पैदा कर रहा है।

■ **महेशचंद्र पुनेठा**

अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अक्सर एक तर्क सुनने में आता है कि आज के जमाने में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है। यह तर्क कुछ इस तरह से दिया जाता है जैसे अंग्रेजी एक भाषा न होकर भूख–प्यास–नींद जैसी कोई

प्राकृतिक आवश्यकता है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। आखिर अंग्रेजी को इतना जरूरी किसने बना दिया? क्यों नहीं चल सकता है इसके बिना काम? यदि सरकार या शासक वर्ग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमारे पास दुनिया के अनेक देशों के उदाहरण हैं, जहां अंग्रेजी शासन, प्रशासन और शिक्षा की भाषा नहीं है बावजूद इसके वे विकास में हमसे मीलों आगे हैं। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसी श्रेणी में आते हैं।

दुनिया के सबसे समृद्ध बीस देशों में से केवल चार देश ही ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी है। तब कैसे माना जाए भला कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है? कितना दुर्भाग्य है कि भारत में आज अंग्रेजी इतनी जरूरी भाषा बन गई कि हर पढ़–लिखे को अपनी पढ़ाई–लिखाई अधूरी लगने लगती है, यदि वह अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है तो। उसे लगता है अपनी भाषा आए या न आए अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। अंग्रेजी का न आना उसके भीतर एक हीनताबोध पैदा कर रहा है।

भारत में दशमलव पांच प्रतिशत से कम लोगों द्वारा अपनी पहली भाषा मानने और अधिकतम पांच प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा को आखिर इतना महत्व क्यों और कैसे मिल गया? यह विचारणीय प्रश्न है।

अगर हम इतिहास में झाकें तो इसकी जड़ें हमें औपनिवेशिक भारत में दिखाई देती हैं। भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने और वैधता दिलाने के लिए यह अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि भारतीयों के एक वर्ग को उसकी संस्कृति से काटा जाए। अपनी भाषा से काट देना संस्कृति से काटने का सबसे बड़ा हथियार होता है। अंग्रेजों ने अपने इस हथियार का भरपूर उपयोग किया। उसी का प्रभाव यह रहा कि देश के आजाद होने के बाद शासन करने का मौका एक ऐसे वर्ग के हाथों में आया जो अंग्रेजीदां था, जिसने भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी को वरीयता प्रदान की। आगे इसी वर्ग का शासन–प्रशासन में वर्चस्व बना रहा। यह क्रम वर्ष 2011 की शुरुआत में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की मुख्य परीक्षा में किए गए बदलाव तक जारी रहा। इसी का परिणाम रहा गत वर्ष हुआ सीसैट विवाद।

सीसैट विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रकाशित एक पुस्तिका 'सीसैट रू विवाद और विकल्प' में मृणालिनी शर्मा सही कहती हैं कि अखिल भारतीय परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी भाषा रखा जाना वह सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते आज अंग्रेजी इतनी जरूरी भाषा बन गई कि उसके बिना सारा ज्ञान अधूरा लगने लगता

है। इसी के कारण देश के गरीब, आदिवासी, ग्रामीण तथा दलित नौजवानों को इन सेवाओं में विशेष अवसर नहीं मिल पाया।

यह तो भला हो कोठारी समिति का, जिसकी सिफारिशों की बदौलत वर्ष 1979 से सिविल सेवा में भारतीय भाषाओं को प्रवेश मिल पाने के कारण गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी तथा ग्रामीण नौजवानों के लिए भी इस सेवा के प्रवेश के दरवाजे खुले, जिनको वर्ष 2011 में सीसैट में अंग्रेजी के प्रभाव को बड़ा कर एक बार फिर बंद करने की कोशिश की जा रही है।

वास्तव में यदि नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं की भाषा अंग्रेजी नहीं होती तो उसके पीछे दौड़ इतनी अंधी नहीं होती। यह कितना अफसोसजनक है कि जिस भाषा को बोलने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा से कम हैं वह देश की तमाम नौकरियों के लिए माध्यम भाषा बनी हुई है। यह लोकत्रंत पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न है।

चिंताजनक बात है कि जहां सीसैट में अंग्रेजी भाषा का प्रश्नपत्र न होने से पहले 45 से 50 प्रतिशत भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए छात्र विशेषकर ग्रामीण आदिवासी अंचलों के मुख्य परीक्षा तक पहुंच जाते थे, अब वे घटकर 15 प्रतिशत से भी नीचे आ गए हैं। इसी तरह तीन वर्ष पहले तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से चुने जाने वाले पहले सौ रैंक में बीस से ज्यादा होते थे, अब एक भी नहीं है। इन सेवाओं से ग्रामीण भारत पूरी तरह बाहर हो गया है। अधिकांश सफल उम्मीदवार शहरी और कोचिंग संस्थानों से निकले हैं।

आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के साथ–साथ देश में अंग्रेजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसका प्रभाव केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं रह गए है, बल्कि शिक्षा और संस्कृति पर भी पड़ रहा है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति से दूर होती जा रही है। अपनी जमीन और उसकी खुशबू से उसका कोई लगाव नहीं रह गया है। गांव और वहाँ रहने वाले लोगों की समस्याओं से वे वाकिफ नहीं हैं। ऐसी पीढ़ी में से ही प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनकर आ रहे हैं।

वास्तव में यदि नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं की भाषा अंग्रेजी नहीं होती तो उसके पीछे दौड़ इतनी अंधी नहीं होती। यह कितना अफसोसजनक है कि जिस भाषा को बोलने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा से कम हैं वह देश की तमाम नौकरियों के लिए माध्यम भाषा बनी हुई है। यह लोकत्रंत पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न है।

आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन अधिकारियों को जनता से उसकी भाषा में संवाद करना तक नहीं आता है, वे कैसे उनके दुख–दर्द को समझेंगे और कैसे उनसे नजदीकी स्थापित करेंगे।

हमारे नीति–नियंता तर्क देते हैं कि अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में एक विकल्प है। विकल्प तो अनुवादक भी हो सकता था। कितना अच्छा होता यदि यह कहा जाता कि एक प्रशासनिक अधिकारी को उस प्रदेश की भाषा सीखने होगी जिस प्रदेश में उसकी नियुक्ति होगी। जैसा कि अलघ समिति ने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि किसी क्षेत्र विशेष के समाज और संस्कृति को जानने के लिए कम–से–कम एक भारतीय भाषा का होना अनिवार्य है। अपनी भाषा बेहतर संवाद करने और तर्कशील चिंतन के लिए भी आवश्यक है। यदि ऐसा होता तो देश की एकता अखंडता और अधिक मजबूत होती तथा जनता से अधिकारी की नजदीकी बढ़ती।

पिछले वर्ष कुछलोग सीसैट विवाद को अंग्रेजी बनाम हिन्दी की लड़ाई बनाने की कोशिश करते रहे। इसके पीछे उनकी चाल थी कि गैर हिंदी भाषा इस लड़ाई से अपने आप को अलग कर लें जबकि वास्तविकता यह थी कि माध्यम चुनने के लिए कम से कम 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों के होने संबंधी शर्त गैर–हिंदी भाषियों के लिए अधिक खतरनाक थी। इसलिए इस लड़ाई इस लड़ाई को न तो अंग्रेजी बनाम हिन्दी कहा जाना चाहिए और अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं, बल्कि यह बराबरी की लड़ाई है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं को भी अंग्रेजी के बराबर महत्व देने की मांग है।

जैसा कि 1979 में कोठारी कमीशन की सिफारिश के बाद सिविल सेवा में किया भी गया। सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं की शुरूआत का ही असर है कि आज इतिहास, राजनीति शास्त्र से लेकर अनेकों विषयों में हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों के हिन्दी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद धड़ाधड़ आ रहे हैं। अनेक राज्यों में स्थापित ग्रंथ अकादमियां भी इस दिशा में सक्रिय हुई है। विदेशी प्रकाशक भी हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में अनुवाद करा रहे हैं। ❑

देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश बढ़ाना

मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती

देश के लोग, व्यापार व उद्योग भुगतान देने व लेने के लिए बैंक का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बैंकों के पास पूंजी की समस्या नहीं रहेगी हालांकि जन धन योजना में बैंक खातों की संख्या में 10 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आधार कार्ड योजना भी चल रही सब्सिडी योजनाओं को नियत व्यक्ति के खाते में डाला जा रहा है जिससे फर्जीवाडा पर प्रतिबंध लगाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सरकार को कर ढांचे में सुधार कर काले धन के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तभी पूंजी निवेश में बढोतरी सम्भव हो सकेगी।

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

मई 26, 2014 को भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रुप में शपथ ली। तबसे ही मोदी के सामने राजनीतिक व आर्थिक बेइंतहा चुनौतियां थी। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण चुनौती देश में पूंजी निवेश को बढाने की है क्योंकि पूंजी निवेश से ही देश में आम आदमी के लिए बढ़ती बेरोजगारी व मंहगाई की समस्यों से निपटा जा सकेगा। पूंजी निवेश में कमी देश में फैले भ्रष्टाचार, आतंकवाद (कर आंतकवाद भी), तकनीकी व बुनियादी आधुनिक अशिक्षा, उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) में पर्याप्त गुणवत्ता का अभाव आदि अनेकों ऐसी समस्याऐं मुँह बाये खडी हुई है कि वे आर्थिक मामलों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे है।

मोदी ने 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत की। मेक इन इंडिया के लिए मोदी को देश में एक सशक्त आर्थिक वातावरण तैयार करने की चुनौती है। मेक इन इंडिया की राह बाधाओं से भरी पड़ी है। इसके तहत ही मैन्युफैक्चरिंग को बढावा देने के लिए कारोबार शुरु करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कवायद शुरु करने की आवश्यकता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वीकार कर बजट में कुछ ठोस उपाय करने की बात कही है।

गत दो वर्ष से विकास दर सुस्त रहने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की चुनौतियां भारी पड रही है जिससे इस क्षेत्र में कारोबार शुरु करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की जरुरत है। इन बाधाओं को दूर करने से ही पूंजी निवेश के लिए बंद पडे दरवाजे खुल सकेंगे।

उधर कर कानूनों में स्थिरता की जरुरत पर भी ध्यान दिया जाना जरुरी है। अल्पकालीन रुप में परिवर्तित होने वाली कर नीतियां मेक इन इंडिया की राह में बडी बाधा साबित हो रही है। कर प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सदृश्य होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के आह्वान पर स्वदेशी व विदेशी निवेशकों ने उत्साह दिखाया। परन्तु देश में होने वाले नये निवेश का आकर वृहत होना जरुरी है। गत सरकार ने कर आंतकवाद का दृश्य खड़ा किया हुआ था तथा समाजवाद के नाम पर कम्युनिज़्म की रीति–नीति को स्वीकार किया गया था जो कि भारतीय माहौल में कतई उचित नहीं थी जिससे विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था।

माना यह जाता है कि देश का आयकर अधिनियम जटिल है व काले धन का निर्माण करने वाला है जिससे निवेशक भारत में आने से हतोत्साहित हो जाते है तथा प्रत्यक्ष कर मामलों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की भूमिका निवेश के वातावरण को बिगाडने की ही रही है। निवेशकों की समस्याओं और शंकाओं का समाधान तत्काल प्रभाव से होना चाहिए तभी विकास की उच्च दर प्राप्त हो सकती है।

देश में प्रत्यक्ष कर के मुकदमों में लगभग 4.36 लाख करोड रुपये की रकम तीन लाख कानूनी विवादों में फंसी हुई है। जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत मुकदमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते है जिनमें सरकार स्वयं वादी है तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड इन मुकदमों को निपटाने में अपनी कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। उसके अपने अधिकार क्षेत्र में 3.74 लाख करोड़ रुपये की राशि फंसी हुई है तथा यह माना जाता है कि 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में प्रत्यक्ष कर बोर्ड हारता है।

सरकार सार्वजनिक व निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ढांचागत व मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की बृद्धि दर बढ़ाने के उपाय कर रही है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां है जिनमें निवेश को बढ़ाना व प्रोत्साहित करना सबसे बड़ी चुनौती है। गत दो वर्षों में विकास की दर मात्र 5 प्रतिशत से नीचे ही रही है। रोजगार के नवीन अवसर कम ही बन पाये है और निवेश का तो अकाल ही पड़ गया। देखा जाए तो वर्ष 1984 के बाद वर्ष 2014 में ही केन्द्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी तथा जनता ने एक निर्णायक व दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति को नेतृत्व करते देखा है। सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण को आगे बढाया जा रहा है। रक्षा व रेलवे सहित कई क्षेत्रों में

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में उदारता दिखाई है। इसी श्रेणी में सरकार ने डीजल की कीमतों को भी नियंत्रण मुक्त करने का फैसला कर लिया है।

अगर 2014 वर्ष का आंकलन करें तो सरकार के अब तक लिए विभिन्न निर्णयों के परिणाम स्वरुप ही सेंसक्स में 6328.74 अंक अर्थात 30 प्रतिशत की तेजी दर्ज हुई। यह वर्ष 2009 के बाद से पांच के दौरान सबसे बड़ी वार्षिक बढ़त दर्ज की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्टाक एक्सचेंजों में लिमिटेड सभी कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 98 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया और अंशों (शेयर) में पूंजी लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गये और उनकी दौलत एक ही वर्ष में 28 लाख करोड़ रुपये से बढ़ गई। उधर निफ्टी में 1978.70 अंक अर्थात लगभग 31 प्रतिशत का उछाल दिखा रहा है। जिससे लगता है कि सरकार के द्वारा लिये गये सभी आर्थिक फैसलों के परिणामस्वरुप पूंजी निवेश सभी स्तरों पर अनिवार्य रुप से बढ़ सकेगा। जनता व पूंजीपति वर्तमान सरकार को पर्याप्त समय दे और उसमें अपना विश्वास रखें।

सरकार कर ढांचे और विशेष कर आय कर अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन करें व कर विवादों को तेजी से निपटा कर उद्योगपतियों को उनका विभिन्न कर विवादों में जमा पैसा शीघ्र वापस लौटाये जिससे कि उद्योगपति उस रकम को उद्योग में लगाकर उद्योग व व्यापार को आगे बढा सके। आयकर विभाग से पैदा होने वाला डर ऊपर तक पंहुच रखने वाले कुछ लोगों को छोड़ कर समूचे व्यावसायिक समुदाय को आंतकित करता है। राजनेता राजनीतिक दुश्मनी के लिए नेताओं, ईमानदार नौकरशाहों और खोजी पत्रकारों के विरुद्ध कर विभागों का प्रयोग किया जाता है। मई 2014 के पश्चात् से हालांकि नये कर मामलों की संख्या नहीं बढ़ पायी है परन्तु बहुत से ऐसे मामले अभी सरकार को गत सरकार से मिले है जिनका जल्दी से जल्दी इनका तत्काल समाधान जरुरी है। अगर वर्तमान सरकार आयकर को समाप्त करने के प्रयास कर देश में बैंकिग ट्रांजेक्शन टैक्स लागू की व्यवस्था इसी प्रकार करें जिस प्रकार अब सरकार जीएसटी लागू करने के लिए कर रही है। इन दोनों कर व्यवस्थाओं से देश में उद्योग, व्यापार व सेवाओं पर लगने वाले दर्जनों करों का उन्मूलन हो सकेगा और देश में काला धन निर्माण का सफाया हो सकेगा। काले धन के रुप में विभिन्न देशों में रुपया जमा करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए व उनकी सारी सम्पत्ति को ही जब्त कर लेना चाहिए। इसी प्रकार देश में छिपे काले धन को बाहर निकालने का प्रयास भी करना होगा।

सरकार क्या यह नहीं देख पा रही है कि बंगलों, कोठियों व महलों को बनाने पर करोड़ों रुपये कहां से आ रहा है? शादियों में व्यय करने के लिए करोड़ों रुपये कहां से आ रहे है? विधायक व सांसद चुने जाने के बाद कुछ ही साल में उनके पास करोड़ों रुपये कहाँ से आ जाते है? विदेशों में ईलाज कराने के बहाने विदेश जा कर काला धन विदेशी बैंकों में जमा करके आना अथवा ईलाज पर ही भारी मात्रा में धन व्यय कर देना जबकि उसी तरह का ईलाज भारत में ही सम्भव होता है तो फिर यह देश के साथ गद्दारी नहीं तो और फिर क्या कहा जा सकता है? देशाटन व पर्यटन के नाम पर विदेशों के दौरे करना क्या उचित है? व उसके लिए धन कहाँ से आया? क्या यह सरकार को नहीं पूछना चाहिए?

सरकार को बड़ी मात्रा में व्यय हो रही धन राशि पर निगाह रखनी चाहिए और हो सके तो 50 रुपये से अधिक के मूल्य के कागजी नोटों का चलन बंद कर देना चाहिए क्योंकि भारत में इस समय 83 प्रतिशत लेन देने 500 व 1000 रुपये के नोटों में होता है तथा इसमें काला धन भी बड़ी मात्रा में होता है। अभी वर्ष 2005 से पूर्व प्रकाशित रुपयों को प्रतिबंधित करने से काम नहीं चलने वाला है और इस योजना में गत दो वर्ष से लगातार तारीख पर तारीख बढती ही जा रही है। काला धन तो अब तक खप गया होगा।

देश के लोग, व्यापार व उद्योग भुगतान देने व लेने के लिए बैंक का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बैंकों के पास पूंजी की समस्या नहीं रहेगी हालांकि जन धन योजना में बैंक खातों की संख्या में 10 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आधार कार्ड योजना भी चल रही सब्सिडी योजनाओं को नियत व्यक्ति के खाते में डाला जा रहा है जिससे फर्जीवाडा पर प्रतिबंध लगाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सरकार को कर ढांचे में सुधार कर काले धन के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तभी पूंजी निवेश में बढोतरी संभव हो सकेगी। ❑

सरकार क्या यह नहीं देख पा रही है कि बंगलों, कोठियों व महलों को बनाने पर करोड़ों रुपये कहां से आ रहा है? शादियों में व्यय करने के लिए करोड़ों रुपये कहां से आ रहे है? विधायक व सांसद चुने जाने के बाद कुछ ही साल में उनके पास करोड़ों रुपये कहाँ से आ जाते है? विदेशों में ईलाज कराने के बहाने विदेश जा कर काला धन विदेशी बैंकों में जमा करके आना अथवा ईलाज पर ही भारी मात्रा में धन व्यय कर देना जबकि उसी तरह का ईलाज भारत में ही सम्भव होता है तो फिर यह देश के साथ गद्दारी नहीं तो और फिर क्या कहा जा सकता है?

समाचार परिक्रमा

नौकरी तलाश रहे लोगों को मिल रही है निराशा

एक सर्वे के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता में नौकरी के नए अवसरों में गिरावट आ रही है जिसकी वजह से अन्य शहरों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वर्ष 2015 के पहले महीने में नए रोजगार का इंडेक्स स्थिर रहा है। रोजगार सलाह देने वाली कंपनी नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के सर्वे के अनुसार जनवरी में 1467 रहा जो पूर्व वर्ष जनवरी 2014 के 1466 के मुकाबले लगभग स्थिर है। हालांकि मासिक आधार पर रोजगार के अवसरों में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि इस दौरान कोलकाता में नौकरियों के नए अवसरों में सबसे अधिक 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जबकि दिल्ली में तीन प्रतिशत की कमी रही और अन्य शहरों में बढ़त देखी गई है। इसके अलावा पुणे में रोजगार के नए अवसरों में सबसे अधिक 14 प्रतिशत और बेंगलुरू में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ❑

तीन मई से शुरू होगी देश भर में एमएनपी सुविधा

अब मोबाइल उपभोक्ता को तीन मई से देशभर में कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा उपभोकताओं को अपना आपरेटर बदलने की सुविधा भी मिलेगी जबकि उनका मोबाइल नंबर वही रहेगा। भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी पर नियमन में संशोधन किया है। फिलहाल उपभोक्ताओं को सिर्फ उनके दूरसंचार सर्किल में ही एमएनपी की अनुमति है। ज्यादातर मामलों में यह राज्य तक सीमित रहता है। ट्राई ने बीते सप्ताह 'दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 में छठा संशोधन जारी किया है। इससे तीन मई, 2015 से देशभर में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी।' ❑

गरीबों की सब्सिडी पर हो रही है अमीरों की मौज

आज जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। देश में खाद्यान्न, ईधन, रेल, उर्वरक और अन्य मदों में सब्सिडी 3.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, लेकिन इस बड़ी राशि में कुछ ही हिस्सा जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। संसद में पेश वर्ष 2014–15 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, 'कीमत सब्सिडी प्रतिगामी है। प्रतिगामी से आशय यह है कि गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी से धनी परिवारों को ज्यादा लाभ हुआ है।' सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दिए जाने की वकालत करते हुए समीक्षा में कहा गया है कि इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा लेकिन इससे सुधारों की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था में खामियों को रेखांकित करते हुए समीक्षा में कहा गया है कि खाद्यान्न सब्सिडी मद में 1,29,000 करोड़ रपए खर्च किए गए जबकि सार्वजनिक वितरण पण्राली (पीडीएस) के तहत आवंटित 54 प्रतिशत गेहूं, 48 प्रतिशत चीनी तथा 15 प्रतिशत चावल का लीकेज हुआ। समीक्षा में मिट्टी के तेल, दाल, बिजली तथा पानी के मामले में भी इसी प्रकार की खामियों को रेखांकित किया गया है। ❑

बिजली, सीमेंट व अन्य चीजें अब होंगी महंगी

सुरेश प्रभु (रेल मंत्री) मालभाड़े में वृद्धि के प्रस्ताव के बाद कोयला, सीमेंट और इस्पात के दामों में वृद्धि होने की आशंका बढ़ गई है। कोयले के लिए मालभाड़े में 6.3 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव से बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए परिवहन लागत बढ़ेगी और बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी। कोल इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार मालभाड़े में वृद्धि का असर कोयले की (लैंडेड) लागत पर हो सकता है। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कहा है कि मालभाड़े में बढोतरी से उत्पादन लागत में 4–5 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। एसोसिएशन आफ पावर प्रोडयूर्स ने कहा कि मालभाड़े में वृद्धि से बिजली की खुदरा शुल्क दरों पर सीधा असर पड़ेगा। यह खान से दूरी पर निर्भर करेगा। बिजली शुल्क दर में लगभग पांच पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि होगी जिसे वहन करना कठिन नहीं होना चाहिए। वही सीमेंट कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार 'उत्पादन लागत 7–10 रपए प्रति बोरी बढ़ जाएगी। यह एक मोटा अनुमान है।' रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा संसद में पेश रेल बजट में कोयला एवं स्लैग का माल ढुलाई भाड़ा क्रमशः 45.70 रपए प्रति टन व 20. 9 रुपए प्रति टन बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही सीमेंट का भी माल ढुलाई भाड़ा 21 रपए प्रति टन बढ़ाने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर इस्पात कंपनियों ने रेल बजट की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस बजट से इस्पात की मांग बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सरकार ने अगले पांच साल में क्षमता निर्माण पर 8. 5 लाख करोड़ रपए खर्च करने की योजना बनाई है। ❑

जीएम बीजों की अनुमति देकर देश की अन्न सुरक्षा को विदेशी कंपनी के हाथों में न सौंपा जाए - स्वदेशी जागरण मंच

दिनांक 8 मार्च 2015 को नागपुर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जेनेटिकली मोडिफाइड अर्थात् जींस परिवर्तन किए गए बीजों के उपयोग की अनुमति देने से देश में खाद्यान्न सुरक्षा का बड़ा संकट निर्माण हो सकता है। इस प्रकार बीजों को प्रोत्साहन देकर सरकार देश को विनाश की ओर न ले जाए। सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने जीएम बीजों का विरोध किया है।

जीएम फसलों से खतरा और समाज पर होने वाले परिणाम विषय पर मार्गदर्शन हेतु कई पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यशाला मं पदाधिकारियों ने सवाल उपस्थित किया कि भाजपा ने जीएम बीजों का विरोध किया था किन्तु अब उसके प्रति अनुकूलता क्यों दिखाई जा रही है। किसानों के हितार्थ किसी भी विषय पर समझौता नहीं किया जाएगा।

अन्न सुरक्षा पर खतरा : कार्यशाला में भारतीय कृषक समाज संगठन के अध्यक्ष डॉ. कृष्णा बीर चौधरी ने कहा कि सात विदेशी कंपनियां जीएम बीजों को लेकर उत्सुक हैं। उनके स्वार्थ के लिए देश की अन्न सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास सरकार न करें। जीएम फसलों को अनुमति देने पर किसानों के बीजों का सार्वभौमत्व पीछे चला जाएगा। मानव सहित वन्यप्राणियों के जीवन पर इन फसलों का दुष्परिणाम हो रहा है। यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी असेसमेंट कमेटी की बैठक में यह मान्य किया गया कि जीएम बीज उत्पादन नहीं बढ़ा सकती है। जीएम को अनुमति देने की बजाए बर्बाद होने वाले अनाज को बचाने की सलाह विशेषज्ञों ने दी थी। डॉ. चौधरी ने कहा कि लोगों को गुमराह कर जीएम को प्रोत्साहित करने का काम रोका जाए। दिलनवाज वारीआवा ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीएम फसलों के खतरे बताए।

जीएम घातक : जीएम बीजों के कारण उत्पादन में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती है। मानव सेहत पर विपरीत परिणाम होता है। अमरीका एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंट के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस पर मुहर लगाई है। मंच ने कार्यशाला के माध्यम से सरकार को आगाह करते हुए कहा कि जीएम बीजों की अनुमति देकर देश की अन्न सुरक्षा को विदेशी कंपनी के हाथों में न सौंपा जाए। ❑

मंच का वार्षिक परिवार सम्मेलन

हम स्वदे□ी विचार और संस्कृति के फायदे और नुकसान को नही समझ पा रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप विदे□ी कम्पनियां अपना पाँव जमाते जा रहे हैं – बंदेशंकर

बीते माह 15 फरवरी 2015 को स्वदे ी जागरण मंच (जमशेदपुर) का वार्शिक परिवार सम्मेलन जुबली पार्क स्थित नर्सरी में संपन्न हुई। इस परिवार सम्मेलन में जम ेदपुर से लगभग 400 लोग सम्मलित हुए। सम्मेलन में मुख्य

अतिथि के रूप में दिल्ली से मंच के राश्ट्रीय संगठक श्री क मीरी लाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित परिचर्चा में अपने विचार रखते हुए श्री कश्मीरी लाल जी ने कहा कि जब भी राश्ट्र के समक्ष चुनौतियां खड़ी हुई है तब तब स्वदे ाी भाव और स्वदे ा प्रेम की बदौलत ही हम ने उन चुनौतियों का सामना किया है। दे ा के बहुसंख्यक समाज (निम्न और मध्य वर्ग) के साथ जब भी अन्याय करने कि कोि ा ा हुई है, स्वदे ाी जागरण मंच और उसके कार्यकर्ता सरकार के उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जुट होकर उनका सामना किया है।

श्री क मीरी लाल ने कहा कि आज टी. वी. सीरियल दे ा के अंदर परिवार तोड़ने का कार्य कर रहे है और इसके माध्यम से विदे ाी संस्कृति और संस्कार का बढ़ावा किया जा रहा है। वै ि वक साजिश के तहत आज परिवार तोड़ने का कार्य के अंर्तगत संस्कार का व्यापार किया जा रहा हे। उन्होने कहा कि 'वैलेन्टाइन डे' पाश्चात्य संस्कृति का कारण है और हमें इससे सतर्क रहने कि आव कता है। आज विदे ाी संस्कृति इस कदर हावी हो गई है कि स्वदे ाी विचारधारा को हम पिछड़ेपन का नि ाानी मानने लगे हैं। उन्होने कहा दे ा में परिवार बचाना जरूरी है, परिवार बचेगा तो हिन्दुस्तान बचेगा।

मंच के पूर्वोतर संघर्श वाहिनी प्रमुख श्री बंदे ांकर सिंह ने कहा कि आज हम दुविधा में हैं जिसके कारण हम स्वदे ाी विचार और संस्कृति के फायदे और नुकसान को नही समझ पा रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप विदे ाी कम्पनियां अपना पाँव जमाते जा रहे हैं।

कार्यक्रम में विशय प्रवे ा कराते हुए मंच के राश्ट्रीय परिशद सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आज भ्रम में पड़कर हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हमें भ्रम में नही रहना चाहिए बल्कि अपने स्वदे ाी पद्धति से अपना कार्य करना चाहिए जिससे परिवार और समाज सुरक्षित रहे। इन्हीं विचारों के आदान–प्रदान करने के लिए हम यह परिवार सम्मेलन का आयोजन करते हैं।

मंच के परिवार सम्मेलन में प्रमुख रूप से सुवोध श्रीवास्तव, जेकेएम राजु, कौ ाल कि ोर अनिल राय, सीपी सिंह, अभय सिंह, जगदेव सिंह, ललीत मेश्राम, के पी चौधरी, रामे वर प्रसाद, सत्यनारायण मिश्र, संजित प्रमाणिक, रौ ान सिंह, नवनीत सिंह, सुखदेव सिंह, अमित मिश्र, मिथले ा प्रसाद, पुरन वर्मा, सुधिर लाल, गौरव भांकर, विमल चरण सिन्हा, इत्यादि सहित अन्य प्रमुख स्वदे ाी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। ❑

स्वदेशी मेले से कुटीर एवं घरेलू उद्यमों को मिलेगा बढ़ावा : वीरेन्द्र सिंह

स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत द्वारा बेनियाब बाग में 14 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही के सांसद वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कुटीर उद्योगों के विकास और इससे जुड़े रोगार को बढ़ाने के लिए प्रयास जरूरी है।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी आन्दोलन चारों युग में हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस सहित अनेक विभूतियों ने देश को आजादी दिलाने में स्वदेशी को ही अपना हथियार बना। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं गांधी जी का चर्खा आन्दोलन स्वदेशी से ही ओत–प्रोत रहा। भारत ऋषि एवं कृषि का देश है हमें अपनी विरासत को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा।

विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि पराधीन को सुख नहीं मिला सकता। हमें अपनी देश की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा तभी हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे।

समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सत्य नारायण मौर्य ने कहा कि ऐसे मेले भारत की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मेलों में सिर्फ विपणन ही नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच संवाद भी कायम होता है और विचारों को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलता है। इस दौरान वेदपाठी छात्रों के वेद–मंत्रोच्चार की सुंदर प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया और भारतीय संस्कृति की अद्भुत परंपरा को जीवन्तमान कर दिया। आखिर दिन भी मेले में खरीदारों की भीड़ रही।

स्वदेशी मेले का शुभारंभ केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया। मेले में खास यह भी था कि रोजाना अलग–अलग विषयों पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाती थी। समापन समारोह के दौरान एमएलसी, कौशल किशोर मिश्रा, देवेन्द्र सिंह, डॉ. अतुल जी और डॉ. अवनीन्द्र राय इत्यादि मौजूद रहे। इसके अलावा देश के कोने–कोने से शिल्पियों ने भी मेले में भाग लिया। ❑